@Kamal.Sandesh KamalSandeshLive kamalsandesh.org kamal.sandesh @KamalSandesh

कमल संदेश

'भाजपा सरकार ने उप्र की जनता को गुंडागर्दी, दंगों और कर्फ्यू से मुक्ति दिलाई'

वर्ष-16, अंक-15 01-15 अगस्त, 2021 (पाक्षिक) ₹20

मंत्रिपरिषद् में बड़ी संख्या में महिला, दलित, आदिवासी व पिछड़ा वर्ग के मंत्रियों का होना गर्व का विषय

शिमला (हिमाचल प्रदेश) में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, मंत्रियों और पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक में भाग लेते भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा

वरिष्ठ भाजपा नेता डॉ. मुरली मनोहर जोशी से नई दिल्ली स्थित उनके आवास पर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा

नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भाजपा राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक को संबोधित करते भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा

रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ स्थित पीजीआई हॉस्पिटल जाकर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री कल्याण सिंह के स्वास्थ्य की जानकारी ली

नई दिल्ली में सहकार भारती के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री रमेश वैद्य के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात करते केंद्रीय गृह तथा सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह

कमल संदेश

पाक्षिक पत्रिका

संपादक
प्रभात झा

कार्यकारी संपादक
डॉ. शिव शक्ति बक्सी

सह संपादक
संजीव कुमार सिन्हा
राम नयन सिंह

कला संपादक
विकास सैनी
भोला राय

डिजिटल मीडिया
राजीव कुमार
विपुल शर्मा

सदस्यता एवं वितरण
सतीश कुमार

इ-मेल
mail.kamalsandesh@gmail.com
mail@kamalsandesh.com
फोन: 011-23381428, फैक्स: 011-23387887
वेबसाइट: www.kamalsandesh.org

विषय-सूची

07 **अब तक 40 करोड़ से ज्यादा लोग कोरोना के खिलाफ लड़ाई में बन चुके हैं 'बाहुबली'**
साथियो, सबका स्वागत है और मैं आशा करता हूं कि आप सबको वैक्सीन का कम से कम एक डोज लग गया होगा। लेकिन उसके बावजूद भी मेरी आप सब मित्रों से प्रार्थना भी है, सदन में भी सभी साथियों से प्रार्थना है कि हम सब कोरोना...

08 **महामारी राजनीति का विषय नहीं होना चाहिए, यह पूरी मानवता के लिए चिंता का विषय है: नरेन्द्र मोदी**
गत 20 जुलाई को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने...

12 **भाजपा सरकार ने राज्य की जनता को गुंडागर्दी, दंगों और कर्फ्यू से मुक्ति दिलाई : जगत प्रकाश नड्डा**
भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने...

24 **भारत की 21वीं सदी की जरूरतें 20वीं सदी के तरीकों से पूरी नहीं की जा सकतीं: नरेन्द्र मोदी**
गत 16 जुलाई को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से गुजरात...

32 **प्रधानमंत्री ने वाराणसी में इंटरनेशनल को-ऑपरेशन एंड कन्वेंशन सेंटर 'रुद्राक्ष' का किया उद्घाटन**
गत 15 जुलाई को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदीं...

वैचारिकी

समाज और विचारधारा / **दीनदयाल उपाध्याय** 17

श्रद्धांजलि

निष्काम कर्मयोगी 'कुशाभाऊ ठाकरे' 19

लेख

विघटनकारी और अवरोधक शक्तियां
भारत की विकास यात्रा को नहीं रोक पायेंगी / **अमित शाह** 10

नयी मोदी कैबिनेट 2.0: सामाजिक रूप से सबसे विविध और समावेशी / **राम प्रसाद त्रिपाठी** 26

अन्य

बड़ी मात्रा में महिला, दलित, आदिवासी मंत्रियों का होना उत्साह, आनंद और गौरव का विषय होना चाहिए: नरेन्द्र मोदी 06

मणिपुर में टीकाकरण अभियान, 'सेवा ही संगठन' और आगामी विधानसभा चुनाव पर चर्चा 11

जीएसटी क्षतिपूर्ति के रूप में राज्यों और विधानसभा वाले केन्द्रशासित प्रदेशों को 75,000 करोड़ रुपये जारी 14

बंगाल में 'कानून का राज' नहीं 22

स्वच्छता और 'मां गंगा' तथा काशी की सुंदरता एक आकांक्षा और प्राथमिकता है: नरेन्द्र मोदी 28

रक्षा मंत्री ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित शिकायत प्रबंधन के एप्लिकेशन का शुभारंभ किया 31

प्रकाशक एवं मुद्रक: डॉ. नन्दकिशोर गर्ग द्वारा मुद्रित, डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास के लिए डॉ. नन्दकिशोर गर्ग द्वारा प्रकाशित, एच.टी. मीडिया लिमिटेड, प्लॉट नं.-8, उद्योग विहार, ग्रेटर नोएडा (उ.प्र.)-201306 से मुद्रित एवं डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पी.पी.-66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली-110003 से प्रकाशित। सम्पादक- प्रभात झा

सोशल मीडिया से

नरेन्द्र मोदी

यूपी में आज सरकार भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद से नहीं, बल्कि विकासवाद से चल रही है। इसीलिए, आज यूपी में जनता की योजनाओं का लाभ सीधा जनता को मिल रहा है, नए-नए उद्योगों का निवेश हो रहा है, रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं।

जगत प्रकाश नड्डा

पश्चिम बंगाल में भाजपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ चुनावी हिंसा को पूरा देश देख रहा है, इस हिंसा में सर्वाधिक अत्याचार महिलाओं, दलितों व बच्चों पर हुआ है। हम सभी लोकतांत्रिक तरीके से लड़ते हुए ममता बनर्जी की तानाशाही मानसिकता को नेस्तनाबूद करेंगे।

अमित शाह

सीमा सुरक्षा ही राष्ट्रीय सुरक्षा है, क्योंकि जिस देश की सीमा सुरक्षित नहीं है वो देश सुरक्षित नहीं है। मोदी सरकार ने सीमांत क्षेत्रों के विकास और वहां से पलायन को रोकने के लिए ढेर सारी योजनाओं की शुरुआत की, इनके तहत दो वर्षों के लिए 888 करोड़ रुपए की विकास योजनाएं शुरू की गई हैं।

राजनाथ सिंह

भाजपा द्वारा आयोजित 'राष्ट्रीय ई-चिंतन सत्र' को सम्बोधित करते हुए 11 जुलाई को राष्ट्रीय सुरक्षा विषय पर विस्तार से चर्चा की। पिछले सात वर्षों में राष्ट्रीय सुरक्षा के मोर्चे पर मोदीजी के नेतृत्व में राजग सरकार ने बड़े प्रतिबद्ध तरीक़े से काम किया है और सफलताओं के नए प्रतिमान गढ़े हैं।

बी.एल. संतोष

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा के लिए ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार को दोषी ठहराया। समाचार रिपोर्टों के अनुसार यह विभिन्न कार्रवाई की सिफारिश करता है। उदारवादियों और समझौतावादी लोगों की घोर चुप्पी। तथाकथित बुद्धिजीवियों की इस बेईमानी पर शर्म आती है।

नितिन गडकरी

मंत्रिमंडल विस्तार के बाद प्रधानमंत्रीजी द्वारा नए मंत्रियों का परिचय कराना संसद की परंपरा रही है। संसदीय परंपराओं का निर्वहन कराना पक्ष और विपक्ष दोनों की ज़िम्मेदारी है। संसद में विपक्ष द्वारा मंत्रियों के परिचय को रोकना संसदीय परंपरा की क्षति है तथा लोकतंत्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है।

मंत्रिपरिषद् में सभी वर्गों का समुचित प्रतिनिधित्व

यह अत्यंत दुर्भाग्यजनक है कि कांग्रेस एवं इसके सहयोगी दलों ने संसद के दोनों सदनों में हंगामा किया, जब प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी अपने मंत्रिपरिषद् का परिचय करा रहे थे। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने ठीक ही कहा कि हाल ही में हुए मंत्रिपरिषद् विस्तार में महिला, पिछड़े, अनु.जा. एवं अनु.ज.जा. समुदाय को भारी प्रतिनिधित्व मिलना शायद विपक्ष को पच नहीं रहा है। ध्यान देने योग्य है कि मंत्रिपरिषद् विस्तार में 11 महिला मंत्री के अलावा पिछड़े वर्ग से 28 मंत्री, अनु.जा. वर्ग से 12 मंत्री, अनु.ज.जा. वर्ग से आठ मंत्री, अल्पसंख्यक समुदाय से पांच मंत्री एवं अन्य वर्गों से 29 मंत्रियों को स्थान मिला है। मोदी सरकार में अब देश के हर वर्गों का इंद्रधनुषी प्रतिनिधित्व तो दिखाई दे ही रहा है, साथ ही अब तक समाज के वंचित, पीड़ित एवं शोषित वर्गों को भी शासन में भागीदारी मिली है। अब तक के सबसे व्यापक प्रतिनिधित्व से युक्त यह मंत्रिपरिषद् विविधतापूर्ण एवं सर्व-समावेशी है। साथ ही, विभिन्न क्षेत्रों की प्रतिभा एवं विशेषज्ञता से युक्त युवा एवं अनुभव का सम्मिश्रण इस मंत्रिपरिषद् में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। इसमें पांच पूर्व मुख्यमंत्री, प्रदेशों के 23 पूर्व मंत्री, 38 पूर्व विधायक, 13 अधिवक्ता, छह चिकित्सक, पांच इंजीनियर, सात पूर्व प्रशासनिक अधिकारी, सात पीएचडी, तीन एमबीए एवं 68 स्नातक हैं। इस मंत्रिपरिषद् में सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों से 25 राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व है। इस प्रकार का समावेशी, प्रतिभा से परिपूर्ण, दक्ष एवं कार्यक्षम, युवा एवं अनुभवी एवं 'नारी शक्ति' से युक्त मंत्रिपरिषद् के सामने कांग्रेस एवं इसके सहयोगी दलों का बुरी तरह से असहज होना स्वाभाविक ही है।

अब तक के सबसे व्यापक प्रतिनिधित्व से युक्त यह मंत्रिपरिषद् विविधतापूर्ण एवं सर्व-समावेशी है। साथ ही, विभिन्न क्षेत्रों की प्रतिभा एवं विशेषज्ञता से युक्त युवा एवं अनुभव का सम्मिश्रण इस मंत्रिपरिषद में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है

कांग्रेस एवं इसके सहयोगी दलों का चेहरा हर दिन देश के सामने बेनकाब हो रहा है। एक ओर जहां कोविड-19 महामारी के विरुद्ध राष्ट्रीय संकल्प को कमजोर करने के लिए इन दलों ने लोगों के मन में संदेह एवं आशंका के बीज डालने के कुप्रयास किए, वहीं दूसरी ओर टीकाकरण अभियान में भी रोड़े डालना का कुचक्र किया। आज जब विश्व का सबसे बड़ा एवं सबसे तेज टीकाकरण अभियान हर दिन गति पकड़ रहा है, कांग्रेस एवं इसके सहयोगी दलों की राजनीति का पर्दाफाश हो चुका है। 23 जुलाई तक के आंकड़ों के अनुसार 43.87 करोड़ टीके पूरे देश में लोगों को लगाए जा चुके हैं। यह कोई नहीं भूल सकता कि कांग्रेस एवं इसके सहयोगी दलों की राज्य सरकारें न केवल टीके उपलब्ध कराने में असफल रहीं, बल्कि केंद्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए बहुमूल्य टीकों की बर्बादी का भी कलंक इनके माथे पर है। जब प्रदेश भाजपा सरकारें अपने राज्यों में निःशुल्क टीका देने का कार्य कर रही थीं तथा केंद्र सरकार 45+ आयुवर्ग के लोगों को निःशुल्क टीके उपलब्ध करा रही थी, गैर भाजपा-शासित राज्यों ने 18-44 आयुवर्ग के लिए टीका उपलब्ध कराने के अपने दायित्व से मुंह मोड़ लिया था। अंततः प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 18-44 आयु वर्ग के लिए निःशुल्क टीकाकरण अभियान की घोषणा की जिसका परिणाम यह है कि पूरे देश में अब तेज गति से टीकाकरण अभियान चल रहा है। टीकों की उपलब्धता एवं गुणवत्ता पर संदेह का वातावरण बनाने वाला प्रोपगेंडा अब लोगों के सामने आ चुका है।

कांग्रेस एवं इसके सहयोगी दल अब देश में अपना नैतिक आधार पूरी तरह से खो चुके हैं। जिस प्रकार से भाजपा कार्यकर्ताओं को तृणमूल कांग्रेस के गुंडों के द्वारा निशाना बनाया गया तथा लूट, हत्या, आगजनी एवं बलात्कार की घटनाएं हुईं, यह सब अब देश के सामने आ चुका है। पश्चिम बंगाल में तृणमूल सरकार, इसका प्रशासन एवं गुंडों के कुकृत्य पर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा कलकत्ता उच्च न्यायालय को दी गई रिपोर्ट से ममता सरकार का लोकतंत्र-विरोधी, अमानवीय एवं बर्बर-चेहरा उजागर हुआ है। अब तक के सबसे भयावह चुनाव के बाद की हिंसा में भाजपा कार्यकर्ताओं पर राजनैतिक बदले की मानसिकता से कई प्रकार के हमले हुए एवं निरपराध लोग इस अमानवीय हिंसा, लूट एवं बलात्कार की भेंट चढ़ गए। कांग्रेस एवं इसके सहयोगी दलों की इस विषय पर सोची-समझी चुप्पी उनके लोकतंत्र-विरोधी एवं अवसरवादी मानसिकता का परिचय देते हैं। देश कांग्रेस एवं इसके सहयोगी दलों को इस अपराधिक कृत्य के लिए कभी क्षमा नहीं करेगा। ■

shivshaktibakshi@kamalsandesh.org

बड़ी मात्रा में महिला, दलित, आदिवासी मंत्रियों का होना उत्साह, आनंद और गौरव का विषय होना चाहिएः नरेन्द्र मोदी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 19 जुलाई को मानसून-सत्र के पहले दिन संसद में अपनी मंत्रिपरिषद् के नये सदस्यों का परिचय कराते समय विपक्षी दलों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कुछ लोगों को यह रास नहीं आ रहा है कि दलित, आदिवासी, पिछड़ा वर्ग और महिला मंत्रियों का यहां परिचय कराया जाए। उन्होंने विपक्षी दलों के रवैये को 'महिला एवं दलित विरोधी मानसिकता' का परिचय करार दिया। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री श्री मोदी ने जब नये मंत्रियों का सदन में परिचय देना शुरू किया, उसी दौरान दोनों सदनों में विपक्षी सदस्यों ने हंगामा किया। यहां प्रस्तुत है श्री मोदी के संबोधन की प्रमुख बातें:

लोक सभा में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने नए मंत्रियों का परिचय कराते हुए कहा कि मैं सोच रहा था कि आज सदन में एक उत्साह का वातावरण होगा, क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में हमारी महिला सांसद मंत्री बनी हैं। आज मुझे खुशी होती कि बहुत बड़ी मात्रा में हमारे दलित भाई मंत्री बने हैं। खुशी होती आज हमारे आदिवासी शिड्यूल ट्राइब्स के सारे साथी बहुत बड़ी मात्रा में मंत्री बने हैं, सबको खुशी होती।

उन्होंने कहा कि इस बार सदन में हमारे साथी सांसद जो किसान परिवार से हैं, ग्रामीण परिवेश के हैं, सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग से हैं, ओबीसी समाज से हैं, बहुत बड़ी मात्रा में उनको मंत्रिपरिषद् में मौका मिला, उनका परिचय करने का आनन्द होता, हर बेंच पर से, बेंच को थपथपा करके उनका गौरव किया गया होता।

इस बार सदन में हमारे साथी सांसद जो किसान परिवार से हैं, ग्रामीण परिवेश के हैं, सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग से हैं, ओबीसी समाज से हैं, बहुत बड़ी मात्रा में उनको मंत्रिपरिषद् में मौका मिला

श्री मोदी ने कहा कि लेकिन शायद देश के दलित मंत्री बने, देश की महिला मंत्री बने, देश के ओबीसी मंत्री बने, देश के किसानों के बेटे मंत्री बने, ये बात कुछ लोगों को रास नहीं आती है और इसलिए उनका परिचय तक नहीं होने देते हैं।

राज्य सभा में नए मंत्रियों का परिचय कराते हुए श्री मोदी ने कहा कि आज एक ऐसा अवसर है सदन का जब देश के गांव के पृष्ठभूमि वाले किसान परिवार के बच्चे आज मंत्री बने हैं और इस सम्मानीय सदन में उनका परिचय हो रहा है तो कुछ लोगों को बड़ी पीड़ा हो रही है।

उन्होंने कहा कि आज इस सदन में महिलाएं जो मंत्री बनी हैं, उनका परिचय हो रहा है। वो कौन-सी महिला विरोधी मानसिकता है कि जिसके कारण इस सदन में उनका नाम भी सुनने को तैयार नहीं हैं, उनका परिचय भी कराने को तैयार नहीं हैं।

श्री मोदी ने कहा कि बहुत बड़ी मात्रा में अनुसूचित जनजाति के हमारे सांसद साथी मंत्री बने हैं। हमारे आदिवासियों के प्रति, ऐसी कौन सी रोष की भावना है कि आदिवासी मंत्रियों का परिचय इस सम्मानीय सदन में हो, ये भी उनको पसंद नहीं आ रहा है।

उन्होंने कहा कि इस सदन में बहुत बड़ी मात्रा में दलित मंत्रियों का परिचय हो रहा है। दलित समाज के प्रतिनिधियों का नाम सुनने को ये तैयार नहीं हैं। ये कौन सी मानसिकता है जो दलितों का गौरव करने को तैयार नहीं हैं, आदिवासियों का गौरव करने को तैयार नहीं, किसान के बेटे का गौरव करने को तैयार नहीं। ये कौन सी मानसिकता है जो महिलाओं का गौरव करने को तैयार नहीं। इस प्रकार की विकृत मानसिकता पहली बार सदन ने देखी है। ■

"अब तक 40 करोड़ से ज्यादा लोग कोरोना के खिलाफ लड़ाई में बन चुके हैं 'बाहुबली"

संसद के मानसून सत्र 2021 की शुरुआत में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 19 जुलाई को कहा कि हम चाहते हैं कि संसद में भी कोरोना महामारी के संबंध में सार्थक चर्चा हो, सबसे प्राथमिकता देते हुए इसकी चर्चा हो। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों से आग्रह करूंगा कि वो तीखे से तीखे सवाल पूछें, धारदार सवाल पूछें लेकिन शांत वातावरण में सरकार को जवाब का मौका भी दें। यहां प्रस्तुत है उनके संबोधन का मूल पाठ:

साथियो, सबका स्वागत है और मैं आशा करता हूं कि आप सबको वैक्सीन का कम से कम एक डोज लग गया होगा। लेकिन उसके बावजूद भी मेरी आप सब मित्रों से प्रार्थना भी है, सदन में भी सभी साथियों से प्रार्थना है कि हम सब कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने में सहयोग दें। अब ये वैक्सीन जो है बाहु पर लगती है और जब वैक्सीन बाहु पर लगती है तो सब 'बाहुबली' बन जाते हैं। और कोरोना के खिलाफ लड़ने के लिए बाहुबली बनने के लिए एक ही उपाय है कि आपके बाहु पर वैक्सीन लगवा दीजिए।

अब तक 40 करोड़ से ज्यादा लोग कोरोना के खिलाफ लड़ाई में बाहुबली बन चुके हैं। आगे भी बहुत तेज गति से इस काम को आगे बढ़ाया जा रहा है। ये ऐसी महामारी है जिसने पूरे विश्व को अपनी चपेट में लिया हुआ है, पूरी मानव जाति को अपनी चपेट में लिया हुआ है और इसलिए हम चाहते हैं कि संसद में भी इस महामारी के संबंध में सार्थक चर्चा हो, सबसे प्राथमिकता देते हुए इसकी चर्चा हो और सारे व्यावहारिक सुझाव सभी माननीय सांसदों से मिलें ताकि महामारी के खिलाफ लड़ाई में बहुत नयापन भी आ सकता है, कुछ कमियां रह गई हों तो उनको भी ठीक किया जा सकता है और इस लड़ाई में सब साथ मिल करके आगे बढ़ सकते हैं।

मैंने सभी फ्लोर लीडर्स से भी आग्रह किया है कि अगर कल शाम को वे समय निकालें तो महामारी के संबंध में सारी विस्तृत जानकारी उनको भी मैं देना चाहता हूं। हम सदन में भी चर्चा चाहते हैं और सदन के बाहर भी सभी फ्लोर लीडर्स से, क्योंकि लगातार मैं मुख्यमंत्रियों से मिल रहा हूं। अलग-अलग फोरम में सब प्रकार की चर्चा हो रही है। तो फ्लोर लीडर्स से भी मैं चाहता हूं कि सदन चल रहा है तो एक सुविधाजनक होगा, रूबरू मिलकर उसकी बात होगी।

ये सदन परिणामकारी हो, सार्थक चर्चा के लिए समर्पित हो, देश की जनता जो जवाब चाहती है वो जवाब सरकार को देने की पूरी तैयारी है। मैं सभी माननीय सांसदों से, सभी राजनीतिक दलों से आग्रह करूंगा कि वो तीखे से तीखे सवाल पूछें, धारदार सवाल पूछें लेकिन शांत वातावरण में सरकार को जवाब का मौका भी दें। ताकि जनता-जनार्दन के पास सत्य पहुंचाने से लोकतंत्र को भी ताकत मिलती है, जनता का भी विश्वास बढ़ता है और देश की प्रगति भी तेज होती है।

ये सत्र अंदर की व्यवस्था पहले की तरह नहीं है, सब साथ बैठकर काम करने वाले हैं क्योंकि करीब-करीब सबका वैक्सीनेशन हो चुका है। मैं फिर एक बार आप सभी साथियों का बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं और आपसे भी आग्रह करता हूं आप खुद को संभालिए और हम सब मिल करके देश की आशा-आकांक्षाओं को पार करने के लिए साथ मिल करके प्रयास करें। ■

प्रधानमंत्री ने दोनों सदनों के नेताओं को महामारी से निपटने के लिए उठाए गए कदमों की दी जानकारी

महामारी राजनीति का विषय नहीं होना चाहिए, यह पूरी मानवता के लिए चिंता का विषय है: नरेन्द्र मोदी

पहले 10 करोड़ खुराक में करीब 85 दिन लगे थे जबकि पिछले 10 करोड़ डोज 24 दिन में ही लग गए

गत 20 जुलाई को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भारत में कोविड-19 के हालात और महामारी के खिलाफ उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी देने के लिए संसद के दोनों सदनों के सभी दलों के नेताओं के साथ बातचीत की। श्री मोदी ने बैठक में भाग लेने और बहुत व्यावहारिक इनपुट और सुझाव देने के लिए सभी नेताओं को धन्यवाद दिया और कहा कि देश के विभिन्न हिस्सों से मिले इनपुट नीति बनाने में काफी मदद करते हैं।

उन्होंने कहा कि महामारी राजनीति का विषय नहीं होना चाहिए, यह पूरी मानवता के लिए चिंता का विषय है। श्री मोदी ने कहा कि मानव जाति ने पिछले 100 वर्षों में ऐसी महामारी नहीं देखी है। प्रधानमंत्री ने देश के हर जिले में एक ऑक्सीजन प्लांट सुनिश्चित करने के लिए किए जा रहे प्रयासों के बारे में भी बताया।

अमेरिका (33.8 करोड़), ब्राजील (12.4 करोड़), जर्मनी (8.6 करोड़), यूके (8.3 करोड़) की तुलना में भारत में सबसे अधिक टीके की खुराक (41.2 करोड़) दी जा चुकी है

श्री मोदी ने नेताओं को भारत के तेजी से बढ़ते टीकाकरण कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कैसे पहले 10 करोड़ खुराक में करीब 85 दिन लगे थे जबकि पिछले 10 करोड़ डोज 24 दिन में ही लग गए। उन्होंने नेताओं को जानकारी दी कि दिन बीतने पर पूरे देश में स्टॉक औसतन 1.5 करोड़ से ज्यादा टीके का रहता है।

लोगों को कोई असुविधा न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए श्री मोदी ने केंद्र सरकार द्वारा इंगित अग्रिम उपलब्धता के आधार पर जिला स्तर पर टीकाकरण अभियान की उचित योजना बनाने

प्रधानमंत्री ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कीं 20 बैठकें

महामारी के दौरान प्रधानमंत्री ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ 20 बैठकें कीं जबकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने राज्यों के साथ 29 बैठकें कीं। केंद्रीय कैबिनेट सचिव ने राज्य के मुख्य सचिवों से 34 बार संवाद किया जबकि 33 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में कोविड-19 प्रबंधन में सहायता के लिए 166 केंद्रीय टीमों को तैनात किया गया।

भारत ने महामारी के दौरान अपनी दवा की उपलब्धता बढ़ा दी। रेमडेसिविर मार्च में 22 जगहों से बनती थी, सीडीएससीओ की मंजूरी से इसे बढ़ाकर जून में 62 कर दिया गया, जिससे उत्पादन क्षमता 38 से बढ़कर 122 लाख शीशी प्रति माह हो गई। इसी तरह, लिपोसोमल एम्फोटेरिसिन के आयात को बढ़ाया गया जिससे आवंटन 45,050 से बढ़कर 14.81 लाख हो गया।

वैसे, अभी मामले घट रहे हैं, पर राज्यों को सलाह दी गई है कि वे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा बताई गई कम से कम 8 दवाओं का बफर स्टॉक बनाए रखें, जिससे भविष्य में कोविड केस बढ़ने पर हालात से निपटा जा सके, ये हैं: एनोक्सापैरिन, मिथाइल प्रेडिनिसोलोन, डेक्सामेथासोन, रेमडेसिविर, टोसीलिजुमैब (कोविड-19 उपचार के लिए), एम्फोटेरिसिन बी डीऑक्सीकोलेट, पॉसकोनाजोल (कोविड-म्यूकरमाइकोसिस केस के लिए), इंट्रावेनस इम्युनोग्लोबुलिन (आईवीआईजी) (बच्चों में मल्टीसिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम के लिए (एमआईएस-सी) आईएस-सी)। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय पूर्वोत्तर राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को खरीद में मदद करेगा।

सदस्यों को भारत की कोविड-19 टीकाकरण रणनीति से भी अवगत कराया गया। इस रणनीति का उद्देश्य है-

- सभी वयस्क भारतीयों को जितनी जल्दी हो सके, सुरक्षित तरीके से मुफ्त टीकाकरण प्रदान करना।
- स्वास्थ्यकर्मियों और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता के आधार पर सुरक्षित करना।
- जोखिम वाली आबादी यानी 45 साल और उससे अधिक को सुरक्षा प्रदान करना (देश में कोविड से संबंधित 80 प्रतिशत मृत्यु इसी आबादी से)।

वैज्ञानिक और महामारी विज्ञान के साक्ष्य और दुनिया की सर्वोत्तम प्रथाओं के आधार पर अभियान के प्रत्येक चरण में नए प्राथमिकता समूहों को टीका कवरेज प्रदान किया गया। यह देश में कोविड-19 टीकों के उत्पादन और उपलब्धता के डायनेमिक मैपिंग पर आधारित है।

अमेरिका (33.8 करोड़), ब्राजील (12.4 करोड़), जर्मनी (8.6 करोड़), यूके (8.3 करोड़) की तुलना में भारत में सबसे अधिक टीके की खुराक (41.2 करोड़) दी जा चुकी है। 1 मई से 19 जुलाई की अवधि में शहरी क्षेत्रों में 12.3 करोड़ (42 प्रतिशत) टीके की खुराक दी गई, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में 17.11 करोड़ (58 प्रतिशत)। इसी अवधि में 21.75 करोड़ पुरुषों (53%), 18.94 करोड़ महिलाओं (47%) और 72,834 अन्य को टीका लगाया गया।

कोविड-19 से भारत की लड़ाई में आगे बढ़ने के तरीके के रूप में परीक्षण, निगरानी, उपचार, टीकाकरण और कोविड उपयुक्त व्यवहार के मार्गदर्शक सिद्धांतों पर प्रकाश डाला गया।

की जरूरत पर बल दिया। उन्होंने कहा कि यह चिंता का विषय है कि टीकाकरण शुरू होने के 6 महीने बाद भी बड़ी संख्या में स्वास्थ्यकर्मियों और फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीका नहीं लग सका है। उन्होंने कहा कि राज्यों को इसके प्रति और अधिक सक्रिय होने की जरूरत है।

कई देशों के हालात को देखते हुए श्री मोदी ने सतर्क रहने की जरूरत पर बल दिया। उन्होंने कहा कि उत्परिवर्तन के कारण इस बीमारी का पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता और इसलिए हम सभी को एक साथ मिलकर इससे लड़ने की जरूरत है। श्री मोदी ने इस महामारी में कोविन और आरोग्य सेतु के रूप में प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करने के भारत के अनूठे अनुभव के बारे में भी बताया।

पूर्व प्रधानमंत्री श्री एचडी देवगौड़ा ने महामारी के दौरान लगातार निगरानी और अथक परिश्रम के लिए प्रधानमंत्री की सराहना की। सभी दलों के नेताओं ने महामारी के दौरान उनके प्रयासों के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। नेताओं ने महामारी को लेकर अपने अनुभवों के बारे में भी बताया। उन्होंने विभिन्न राज्यों के हालात पर प्रकाश डाला और अपने-अपने राज्यों में टीकाकरण अभियान के बारे में बताया। उन्होंने लगातार कोविड उपयुक्त व्यवहार सुनिश्चित करने की जरूरत बताई। नेताओं ने दिए गए प्रजेंटेशन की समग्र जानकारी को लेकर सराहना की।

स्वास्थ्य सचिव श्री राजेश भूषण ने विस्तृत प्रजेंटेशन दिया। उन्होंने बताया कि आज की तारीख में केवल 8 राज्यों में 10 हजार से ज्यादा मामले हैं जिनमें ज्यादातर महाराष्ट्र और केरल राज्य से हैं। सिर्फ 5 राज्यों में पॉजिटिविटी रेट 10 प्रतिशत से अधिक है। ■

विघटनकारी और अवरोधक शक्तियां भारत की विकास यात्रा को नहीं रोक पायेंगी

अमित शाह
केन्द्रीय गृहमंत्री एवं सहकारिता मंत्री

विघटनकारी और अवरोधक शक्तियां अपने षड्यंत्रों से भारत की विकास यात्रा को नहीं रोक पायेंगी। मानसून सत्र देश में विकास के नये मापदंड स्थापित करेगा। संसद का मानसून सत्र शुरू हुआ और आज के घटनाक्रम को पूरे देश ने देखा। देश के लोकतंत्र को बदनाम करने के लिए मानसून सत्र से ठीक पहले कल देर शाम एक रिपोर्ट आती है, जिसे कुछ वर्गों द्वारा केवल एक ही उद्देश्य के साथ फैलाया जाता है कि कैसे भारत की विकास यात्रा को पटरी से उतारा जाए और अपने पुराने नैरेटिव के तहत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत को अपमानित करने के लिए जो कुछ भी करना पड़े किया जाए।

इस मानसून सत्र से देशवासियों की ढ़ेरों अपेक्षाएं और उम्मीदें जुड़ी हैं। देश के किसानों, युवाओं, महिलाओं और समाज के गरीब व वंचित वर्ग के कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण विधेयक सदन में सार्थक बहस और चर्चा के लिए तैयार हैं। कल सर्वदलीय बैठक और आज सुबह सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले भी प्रधानमंत्रीजी ने सभी विपक्षी दलों के नेताओं को स्वयं आश्वासन देते हुए कहा कि सरकार सदन में सभी विषयों पर चर्चा करने के लिए तैयार है।

अभी कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्रीजी द्वारा केंद्रीय मंत्रिपरिषद् का विस्तार किया गया जिसमें देश के हर कोने से समाज के हर वर्ग विशेषकर महिलाओं, किसान, दलित और पिछड़े वर्ग से चुनकर आए सदस्यों को विशेष प्रतिनिधित्व दिया गया। लेकिन, कुछ ऐसी देशविरोधी ताकतें हैं जो मोदी जी द्वारा महिलाओं और समाज के पिछड़े व वंचित वर्ग को दिए गए सम्मान को पचा नहीं पा रही हैं। ये वही लोग हैं जो निरंतर देश की प्रगति को बाधित करने का प्रयास करते रहते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि ये लोग किसके इशारे पर भारत की छवि को धूमिल करने का काम कर रहे हैं? उन्हें बार-बार भारत को नीचा दिखाने में क्या ख़ुशी मिलती है? अपना जनाधार व राजनीतिक महत्व खो चुकी कांग्रेस को इसमें कूदते देखना न तो अप्रत्याशित लगता है और ना ही आश्चर्यजनक। कांग्रेस के पास लोकतंत्र को कुचलने का अच्छा अनुभव है। लोकतंत्र एवं विकास की अवरोधक कांग्रेस खुद आंतरिक कलह से जूझ रही है इसलिए वो संसद में आने वाले किसी भी प्रगतिशील कार्य को पटरी से उतारने की हर सम्भव कोशिश कर रही है।

आज जब प्रधानमंत्री जी लोकसभा और राज्यसभा में अपने नये मंत्रिपरिषद् का परिचय कराने के लिए उठे, जो संसद की एक पुरानी व समृद्ध परंपरा है, तो कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्ष के नेताओं ने दोनों सदनों के वेल में आकर सदन की कार्यवाही की बाधित किया। क्या वो हमारे लोकतंत्र के मंदिर और उसकी गरिमा का ऐसे ही सामान करते हैं? यही व्यवहार उन्होंने तब भी जारी रखा जब सूचना एवं प्रसारण मंत्री इस मुद्दे पर बोलने के लिए आये।

कुछ विघटनकारी वैश्विक संगठन हैं जो भारत की प्रगति को पसंद नहीं करते हैं। ये अवरोधक भारत के वो राजनीतिक षड्यंत्रकारी हैं जो नहीं चाहते कि भारत प्रगति कर आत्मनिर्भर बने। भारत की जनता इस क्रोनोलोजी और रिश्ते को बहुत अच्छे से समझती है

इस वाक्य को अक्सर लोग हल्के-फुल्के अंदाज में मेरे साथ जोड़ते रहे हैं, लेकिन आज मैं गंभीरता से कहना चाहता हूं- इस तथाकथित रिपोर्ट के लीक होने का समय और फिर संसद में ये व्यवधान... आप क्रोनोलोजी समझिये!

यह भारत के विकास में विघ्न डालने वालों की भारत के विकास के अवरोधकों के लिए एक रिपोर्ट है। कुछ विघटनकारी वैश्विक संगठन हैं जो भारत की प्रगति को पसंद नहीं करते हैं। ये अवरोधक भारत के वो राजनीतिक षड्यंत्रकारी हैं जो नहीं चाहते कि भारत प्रगति कर आत्मनिर्भर बने। भारत की जनता इस क्रोनोलोजी और रिश्ते को बहुत अच्छे से समझती है।

मैं देश की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं कि मोदी सरकार की प्राथमिकता स्पष्ट है – 'राष्ट्रीय कल्याण' और हम इसकी सिद्धि के लिए निरंतर कार्य करते रहेंगे चाहे कितनी भी बाधाएं आयें। ■

मणिपुर में टीकाकरण अभियान, 'सेवा ही संगठन' और आगामी विधानसभा चुनाव पर चर्चा

मणिपुर भाजपा कोर कमेटी की बैठक 03 जुलाई, 2021 को इम्फाल में संपन्न हुई। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री (संगठन) श्री बी.एल. संतोष ने राज्य कोर कमेटी की बैठक में भाग लिया और उसे संबोधित किया। इसमें मणिपुर के मुख्यमंत्री श्री एन बीरेन सिंह, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ए शारदा देवी, भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं राज्य प्रभारी श्री संबित पात्रा और भाजपा पूर्वोत्तर प्रभारी श्री अजय जामवाल ने भाग लिया। इसके अतिरिक्त अन्य वरिष्ठ नेताओं में भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष श्री थ चाओबा और श्री क्ष भवनंदा, सांसद श्री आरके रंजन और लीशेम्बा सनजाओबा और राज्य मंत्री श्री थ बिस्वजीत भी उपस्थित थे।

समिति के सदस्यों संबोधित करते हुए श्री बी.एल. संतोष ने राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव पर बात करते हुए 12वें विधानसभा चुनावों में पार्टी की जीत सुनिश्चित करने के लिए उठाए जाने वाले कदमों पर चर्चा की, जो कि 2022 की शुरुआत में होने वाले हैं। उन्होंने कोविड 19 के खिलाफ टीकाकरण अभियान और मणिपुर में 'सेवा ही संगठन' की प्रगति पर भी चर्चा की।

श्री बीएल संतोष ने सभी से बिना किसी झिझक के टीका लगवाने की अपील की। उन्होंने कहा कि टीकाकरण ही वायरस से लड़ने का एकमात्र साधन है।

इस बैठक के बाद मणिपुर भाजपा अध्यक्ष श्रीमती ए शारदा देवी ने एक प्रेस वार्ता में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा को प्रदेश भाजपा अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करने के लिए उनका धन्यवाद दिया।

भाजपा सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए श्रीमती ए शारदा ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री एन बीरेन सिंह के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार के आने के बाद से राज्य में इनर लाइन परमिट सिस्टम (आईएलपीएस) को लागू करने की लंबित मांग को पूरा किया गया, जिससे राज्य के नागरिक अधिक सुरक्षित महसूस कर रहे हैं।

उन्होंने आगे कहा कि भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार के आने से राज्य में बार-बार बंद और नाकेबंदी की घटनाओं में भी कमी आयी है।

भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री (संगठन) श्री बी.एल. संतोष ने इम्फाल में अपने प्रवास के दौरान राज्य इकाई के नेताओं, भाजपा विधायकों और पदाधिकारियों से आगामी विधानसभा चुनाव के लिए रणनीति बनाने को लेकर मुलाकात की।

बाद में एक ट्वीट में श्री बी.एल. संतोष ने कहा, " भाजपा मणिपुर इकाई की कोर कमेटी की बैठक प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती शारदा देवी, मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह और राज्य प्रभारी संबित पात्रा की उपस्थिति में आयोजित की गई। हमने टीकाकरण अभियान, 'सेवा ही संगठन' और आगामी विधानसभा चुनावों पर चर्चा की। ■

भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय पदाधिकारी घोषित

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा की सहमति से भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री तेजस्वी सूर्या ने 14 जुलाई को मोर्चा के राष्ट्रीय पदाधिकारियों के नामों की घोषणा की। श्री अनूप कुमार साहा, श्री मधुकेश्वर देसाई, श्री मनीष सिंह, सुश्री अर्पिता अपराजिता बड़जेना, श्री राम सतपुते, डॉ. अभिनव प्रकाश एवं श्रीमती नेहा जोशी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए हैं जबकि श्री राजू बिष्टा, श्री रोहित चहल एवं श्री वैभव सिंह को राष्ट्रीय महामंत्री का दायित्व दिया गया है। श्री श्याम राज, कु. शहजादी सैय्यद, श्री रवि भगत, श्री तेजिंदर पाल सिंह बग्गा, श्री गौरव गौतम, श्री अरुण ज्योति हजारिका एवं श्री निन्थोंजम मौगपोकंगंबा को राष्ट्रीय मंत्री नियुक्त किया गया है। श्री साईं प्रसाद को कोषाध्यक्ष, श्री विनीत त्यागी को कार्यालय प्रभारी, श्री अमनदीप सिंह को मीडिया प्रभारी एवं श्री कपिल परमार को सोशल मीडिया प्रभारी बनाया गया है एवं श्री वरुण झावेरी को पॉलिसी एंड रिसर्च की जिम्मेदारी मिली है। ■

भाजपा के नये राष्ट्रीय प्रवक्ता

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने 21 जुलाई को श्री प्रेम शुक्ल, मुंबई तथा श्रीमती शाजिया इल्मी, दिल्ली को पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता नियुक्त किया। भाजपा राष्ट्रीय महामंत्री एवं मुख्यालय प्रभारी श्री अरुण सिंह ने प्रेस-विज्ञप्ति जारी कर यह जानकारी दी। ■

भाजपा सरकार ने राज्य दंगों और कर्फ्यू से मुक्ति

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने 16 जुलाई, 2021 को भाजपा, उत्तर प्रदेश कार्यसमिति बैठक को वर्चुअली संबोधित किया और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार की सराहना करते हुए नकारात्मक राजनीति करने के लिए विपक्ष पर जमकर प्रहार किया।

विकास के मायने में बना उत्तर प्रदेश देश का अग्रणी राज्य

श्री नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश आज विकास के 'एक्सप्रेस-वे' पर तेज गति से आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्रीजी के नेतृत्व में पूरे देश में विकास रूपी परिवर्तन की बयार चल रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने नेतृत्व से उत्तर प्रदेश के विकास को नई दृष्टि और दिशा दी है।

कोविड प्रबंधन

श्री नड्डा ने कहा कि कोरोना के सामने पूरी दुनिया ने एक तरह से घुटने टेक दिए जबकि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने समय पर साहसिक निर्णय लेते हुए 130 करोड़ देशवासियों की रक्षा की। कोरोना की शुरुआत में जहां देश में केवल एक ही टेस्टिंग लैब हुआ करती थी, वही आज देश में 2500 टेस्टिंग लैब्स हैं। पहले जहां हमारी क्षमता केवल 1500 टेस्टिंग प्रतिदिन की थी, वहीं आज 25 लाख प्रतिदिन की है। आज आइसोलेशन बेड्स, आईसीयू बेड्स और ऑक्सीजन बेड्स की कहीं कोई कमी नहीं है। उत्तर प्रदेश में भाजपा की योगी आदित्यनाथ सरकार ने 'टेस्ट, ट्रेस और ट्रीट' की रणनीति के सहारे काफी सराहनीय काम किया है। प्रदेश में अब तक 5.70 करोड़ सैम्पल की टेस्टिंग हुई है जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। आज उत्तर प्रदेश में औसतन डेढ़ लाख टेस्टिंग प्रतिदिन हो रही है। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 1,260 टेस्टिंग सेंटर काम कर रहे हैं।

टीकाकरण

टीकाकरण पर चर्चा करते हुए श्री नड्डा ने कहा कि इस वर्ष दिसंबर तक हमारे पास 135 करोड़ कोविड वैक्सीन डोज उपलब्ध होगी। हमारा टीकाकरण कार्यक्रम दुनिया का 'लार्जेस्ट और फास्टेस्ट' वैक्सीनेशन प्रोग्राम है। 21 जून से जब सबके लिए 'फ्री वैक्सीनेशन' की शुरुआत हुई, तब पहले ही दिन उत्तर प्रदेश में 7.68 लाख वैक्सीन डोज लगाए गए हैं। अब तक यूपी में लगभग 3.88 करोड़ वैक्सीन डोज लगाए जा चुके हैं। इसमें 3.22 करोड़ फर्स्ट डोज और 66 लाख सेकंड डोज लगाए गए हैं।

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना

श्री नड्डा ने कहा कि कोरोना के समय गरीबों के कल्याण के लिए और उनके दो वक्त की रोटी की चिंता करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पिछले वर्ष अप्रैल से लेकर नवंबर तक देश के 80 करोड़ लोगों के लिए मुफ्त राशन की व्यवस्था की थी। पिछले वर्ष की ही भांति इस वर्ष भी प्रधानमंत्रीजी ने अप्रैल माह से नवंबर तक देश के 80 करोड़ लोगों के लिए मुफ्त राशन की व्यवस्था की है। इस कार्यक्रम को पार्टी कार्यकर्ता अपना कार्यक्रम बनाएं और अंतिम व्यक्ति तक राशन पहुंचे, इसकी व्यवस्था करें। पिछले महीने उत्तर प्रदेश सरकार ने 4,41,576 मीट्रिक टन गेहूं और 2,94,384 मीट्रिक टन चावल उठाया है। 'वन नेशन, वन कार्ड' के तहत राशन वितरण में भी पार्टी कार्यकर्ता अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं।

उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत लगभग तीन लाख करोड़ रुपये एमएसएमई सेक्टर के लिए, एक लाख करोड़ रुपये एग्री इन्फ्रॉस्ट्रक्चर के लिए और 5 लाख करोड़ रुपये 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स के कल्याण के लिए निर्धारित किये गए हैं। इसका लाभ उद्यमियों, किसानों और जरूरतमंदों को मिले, हमें इसका ध्यान रखना चाहिए।

आयुष्मान भारत योजना

श्री नड्डा ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना देश के गरीबों के लिए

की जनता को गुंडागर्दी, दिलाई : जगत प्रकाश नड्डा

वरदान बन चुकी है। अब तक आयुष्मान भारत योजना से 1.80 करोड़ लोग लाभान्वित हो चुके हैं और इस पर अब तक लगभग 23 हजार करोड़ खर्च किये जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश में लगभग 7 लाख लोगों को इसका लाभ मिला है और इस पर लगभग 735 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। साथ ही, प्रदेश में मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान से गरीबों का कल्याण हो रहा है। अगर आज भाजपा न होती, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी न होते तो क्या होता? केवल सात सालों में देश में ये परिवर्तन आया है।

उत्तर प्रदेश में बदलाव की कहानी

श्री नड्डा ने कहा कि पहले 'बीमारु' राज्य की चर्चा होती थी जिसमें बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश का नाम आता था। हमने इस श्रेणी से राज्यों को बाहर निकालकर विकास के पथ पर अग्रसर किया है।

- 2014 में उत्तर प्रदेश का बजट 2 लाख करोड़ रुपये का था, आज यह 5.5 लाख करोड़ रुपये का है।
- 2014 में वैट कलेक्शन लगभग 12,000 करोड़ रुपये का था, जो आज बढ़कर लगभग 49 हजार करोड़ रुपये हो गया है।
- उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार आने से पहले देश के जीडीपी में उत्तर प्रदेश का योगदान 10.90 लाख करोड़ रुपये का हुआ करता था जो आज बढ़कर 21.73 लाख करोड़ रुपये हो गया है।
- ईज ऑफ़ डूइंग बिजनेस में आज उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर आ गया है।
- 2014-15 में उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 47,116 रुपये थी जो आज बढ़कर 94,495 रुपये हो गई है।
- उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर रोजगार का सृजन हो रहा है। अगले चार महीने में ही लगभग 90 हजार युवाओं को रोजगार दे दिए जाने की संभावना है।
- पिछले चार वर्षों में उत्तर प्रदेश में एक भी दंगे नहीं हुए।
- पहले 'एक्सप्रेस' और उत्तर प्रदेश कहीं मेल नहीं खाते थे लेकिन आज हर तरफ प्रदेश में एक्सप्रेस-वे का जाल बिछाया जा रहा है। पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे, गंगा एक्सप्रेस हाइवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे, बलिया लिंक एक्सप्रेस सहित कई मार्गों पर काम चल रहा है। रोड कनेक्टिविटी और एयर कनेक्टिविटी में प्रदेश ने काफी बड़ी छलांग लगाई है।
- फिल्म सिटी का काम जोर-शोर से चल रहा है।
- उत्तर प्रदेश इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के रूप में प्रतिष्ठित हो रहा है।
- 'मेक इन इंडिया', वन डिस्ट्रिक्ट-वन प्रोडक्ट और मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह जैसी योजनाओं से राज्य का कायाकल्प हो रहा है।
- उद्योगों के विकास के लिए 56,754 छोटे उद्यमियों को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लगभग 2,000 करोड़ रुपये की मदद दी गई है।

हमारा एक ही मंत्र है - 'सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास'

श्री नड्डा ने कहा कि जातिवाद, दंगे, गुंडागर्दी और माफिया राज के रूप में जाने जाना वाला उत्तर प्रदेश आज विकास के अग्रदूत के रूप में जाना जाता है। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश की भाजपा सरकार ने राज्य की जनता को गुंडागर्दी, दंगों और कर्फ्यू से मुक्ति दिलाई है। मैं इसके लिए प्रदेश की भाजपा सरकार, योगी आदित्यनाथ और उनके मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों को बधाई देता हूं। उन्होंने उत्तर प्रदेश की तसवीर और तकदीर बदलने में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ी।

इस बैठक में उत्तर प्रदेश से प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री स्वतंत्रदेव सिंह, मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश प्रभारी श्री राधामोहन सिंह, उप-मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य, उप-मुख्यमंत्री श्री दिनेश शर्मा, प्रदेश संगठन महामंत्री श्री सुनील बंसल सहित वरिष्ठ पार्टी पदाधिकारी, मंत्री और कार्यसमिति के सदस्य उपस्थित थे, जबकि दिल्ली में श्री नड्डा के साथ केंद्रीय मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी, केंद्रीय मंत्री श्री महेंद्र नाथ पांडेय एवं भाजपा राष्ट्रीय महामंत्री श्री अरुण सिंह के साथ-साथ कई केंद्रीय मंत्री, सांसद, विधायक, पदाधिकारी एवं कार्यसमिति के सदस्य उपस्थित थे। ■

जीएसटी क्षतिपूर्ति के रूप में राज्यों और विधानसभा वाले केन्द्रशासित प्रदेशों को 75,000 करोड़ रुपये जारी

केन्द्रीय वित्त मंत्रालय ने जीएसटी क्षतिपूर्ति के बदले में दी गई बैक-टू-बैक ऋण सुविधा के तहत राज्यों और विधानसभा वाले केन्द्रशासित प्रदेशों को 15 जुलाई को 75,000 करोड़ रुपये की धनराशि जारी कर दी। यह वास्तविक उपकर संग्रह में से हर 2 महीने में जारी की जा रही सामान्य जीएसटी क्षतिपूर्ति के अतिरिक्त धनराशि है।

28 मई, 2021 को हुई 43वीं जीएसटी परिषद की बैठक के बाद यह फैसला लिया गया था कि केन्द्र सरकार 1.59 लाख करोड़ रुपये का ऋण लेगी और क्षतिपूर्ति कोष में अपर्याप्त धनराशि के मद्देनजर कम जारी की गई क्षतिपूर्ति के कारण संसाधन की कमी को पूरा करने के लिए बैक-टू-बैक आधार पर राज्यों और विधानसभा वाले केन्द्रशासित प्रदेशों को जारी करेगी।

यह धनराशि वित्त वर्ष 2020-21 में इसी तरह की सुविधा के लिए अपनाए गए सिद्धांतों के अनुसार है, जहां ऐसी ही व्यवस्था के तहत राज्यों को 1.10 लाख करोड़ रुपये जारी किए गए थे। 1.59 लाख करोड़ रुपये की यह धनराशि 1 लाख करोड़ रुपये (उपकर संग्रह के आधार पर) से ज्यादा की क्षतिपूर्ति के अतिरिक्त होगी, जो इस वित्त वर्ष के दौरान विधानसभा वाले राज्यों/यूटी को जारी किए जाने का अनुमान है। कुल 2.59 लाख करोड़ रुपये की धनराशि वित्त वर्ष 2021-22 में जीएसटी क्षतिपूर्ति की राशि से ज्यादा होने का अनुमान है।

सभी पात्र राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों (विधानसभा वाले) ने बैक-टू-बैक ऋण सुविधा के तहत क्षतिपूर्ति की कमी की भरपाई की व्यवस्था पर सहमति दी है। कोविड-19 महामारी पर प्रभावी प्रतिक्रिया और प्रबंधन व पूंजी व्यय के लिए सभी राज्यों को बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों को उनके प्रयास में सहायता के लिए वित्त मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2021-22

के दौरान बैक-टू-बैक ऋण सुविधा के तहत सहायता जारी करने में अग्रणी रहते हुए आज एक किस्त में 75,000 करोड़ रुपये (पूरे साल के दौरान कुल कमी का लगभग 50 प्रतिशत) जारी कर दिए हैं। शेष धनराशि 2021-22 की दूसरी छमाही में नियमित रूप से किस्तों में जारी कर दी जाएगी।

75,000 करोड़ रुपये की धनराशि का भारत सरकार द्वारा वर्तमान वित्त वर्ष में जारी 5 साल की प्रतिभूतियों से कुल 68,500 करोड़ रुपये और 2 साल की प्रतिभूतियों से 6,500 करोड़ रुपये का वित्तपोषण किया जा रहा है, जो क्रमशः 5.60 प्रतिशत और 4.25 प्रतिशत भारित औसत आय वाली हैं।

यह अनुमान है कि इस धनराशि से राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों को अन्य कामों के अलावा स्वास्थ्य इन्फ्रास्ट्रक्चर में सुधार और इन्फ्रॉस्ट्रक्चर परियोजनाओं को आगे बढ़ाने में अपने सार्वजनिक व्यय की योजना बनाने में मदद मिलेगी। ■

कैबिनेट ने महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में वृद्धि को दी मंजूरी

कैबिनेट समिति ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में 14 जुलाई को केंद्र सरकार के कर्मचारियों को दिए जाने वाले महंगाई भत्ते और पेंशनभोगियों को दी जाने वाली महंगाई राहत को 01 जुलाई, 2021 से बढ़ाकर 28% करने की मंजूरी दे दी, जो मूल वेतन/पेंशन के 17% की मौजूदा दर में 11% की वृद्धि को दर्शाता है।

कोविड-19 महामारी से उत्पन्न हुई अप्रत्याशित स्थिति को देखते हुए केंद्र सरकार के कर्मचारियों को दिए जाने वाले महंगाई भत्ते (डीए) और पेंशनभोगियों को दी जाने वाली महंगाई राहत (डीआर) की तीन अतिरिक्त किस्तों, जो 01 जनवरी, 2020, 01 जुलाई, 2020 और 01 जनवरी, 2021 से देय थीं, पर रोक (फ्रीज) लगा दी गई थी।

अब सरकार ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों को दिए जाने वाले महंगाई भत्ते और पेंशनभोगियों को दी जाने वाली महंगाई राहत को 01 जुलाई, 2021 से बढ़ाकर 28% करने का निर्णय लिया, जो मूल वेतन/पेंशन के 17% की मौजूदा दर में 11% की वृद्धि को दर्शाता है। यह वृद्धि 01 जनवरी, 2020, 01 जुलाई, 2020 और 01 जनवरी, 2021 को देय अतिरिक्त किस्तों को दर्शाती है। 01 जनवरी, 2020 से लेकर 30 जून, 2021 तक की अवधि के लिए महंगाई भत्ता/महंगाई राहत की दर 17% पर ही यथावत रहेगी। ■

केंद्र प्रायोजित योजना 'राष्ट्रीय आयुष मिशन' को जारी रखने की मिली मंजूरी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में 14 जुलाई को राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) को केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में 01 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2026 तक 4607.30 करोड़ रुपये (केंद्रीय हिस्से के रूप में 3,000 करोड़ रुपये और राज्य के हिस्से के रूप में 1607.30 करोड़ रुपये) के वित्तीय व्यय के साथ जारी रखने को मंजूरी दे दी। आयुष मिशन 15 सितंबर, 2014 को शुरू किया गया था।

भारत के पास आयुर्वेद, सिद्ध, सोवा-रिग्पा, यूनानी और साथ ही होम्योपैथी (एएसयू एंड एच) जैसी पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों का प्रतिनिधित्व करने वाली एक अद्वितीय विरासत है जो निवारक, प्रोत्साहक और उपचारात्मक स्वास्थ्य सेवा के लिए ज्ञान का खजाना है।

भारतीय चिकित्सा पद्धतियों की विशेषताएं यानी उनकी विविधता एवं लचीलापन; सुगम्यता; वहन योग्य, आम जनता के एक बड़े वर्ग द्वारा व्यापक स्वीकृति; तुलनात्मक रूप से कम लागत और बढ़ते आर्थिक मूल्य, उन्हें वैसे स्वास्थ्य सेवा प्रदाता बनने की क्षमताओं से भरती हैं जिनकी हमारे एक बड़े वर्ग को जरूरत है।

केंद्र प्रायोजित योजना 'राष्ट्रीय आयुष मिशन' को आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सस्ती आयुष सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से लागू किया जा रहा है। इसका उद्देश्य आयुष अस्पतालों और औषधालयों के उन्नयन के माध्यम से व्यापक पहुंच के साथ, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी), सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) और जिला अस्पतालों (डीएच) में आयुष सुविधाओं को एक साथ मुहैया करना, आयुष शैक्षणिक संस्थानों के उन्नयन के माध्यम से राज्य स्तर पर संस्थागत क्षमता को मजबूत करना, 50 बिस्तरों वाले एकीकृत आयुष अस्पताल की स्थापना, आयुष सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम और 12,500 आयुष स्वास्थ्य एवं वेलनेस सेंटर का संचालन करना है।

इनके पीछे मकसद आयुष सिद्धांतों और प्रथाओं के आधार पर एक समग्र वेलनेस मॉडल की सेवाएं प्रदान करना है ताकि रोग के बोझ को कम कर और जेब पर पड़ने वाले खर्च को कम करके 'स्व-देखभाल' के लिए जनता को सशक्त बनाया जा सके।

मिशन देश में विशेष रूप से पिछड़े और दूर-दराज के क्षेत्रों में आयुष स्वास्थ्य सेवाएं/शिक्षा प्रदान करने के लिए राज्य/केंद्रशासित प्रदेशों की सरकारों के प्रयासों का समर्थन करके स्वास्थ्य सेवाओं की खामियों को दूर कर रहा है। एनएएम के तहत ऐसे क्षेत्रों की विशिष्ट जरूरतों और उनकी वार्षिक योजनाओं में उच्च संसाधनों के आवंटन पर विशेष ध्यान दिया जाता है।

मिशन से निम्नलिखित परिणाम मिलने की उम्मीद है:

i) आयुष सेवाओं एवं दवाओं की बेहतर उपलब्धता एवं प्रशिक्षित श्रमबल प्रदान कर बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के माध्यम से आयुष स्वास्थ्य सेवाओं तक बेहतर पहुंच।

ii) बेहतर सुविधाओं से लैस बहुत सारे आयुष शिक्षण संस्थानों के माध्यम से आयुष शिक्षा में सुधार।

iii) आयुष स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों का इस्तेमाल करते हुए लक्षित सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों के माध्यम से संचारी/गैर-संचारी रोगों को कम करने पर ध्यान केंद्रित। ■

देश के एक लाख गांवों और 50 हजार ग्राम पंचायतों में 'हर घर जल' का लक्ष्य हासिल

जल जीवन मिशन ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 2024 तक देश के हर घर में नल का स्वच्छ पानी उपलब्ध कराने के सपने को पूरा करते हुए 14 जुलाई को 23 महीने की छोटी अवधि में एक लाख गांवों में हर घर में नल के पानी की आपूर्ति करने का ऐतिहासिक मुकाम हासिल कर लिया।

'जल जीवन मिशन' ने तेज रफ्तार के साथ और व्यापक स्तर पर काम करते हुए पिछले 23 महीने में 4.5 करोड़ घरों में नल के पानी की आपूर्ति की

इस महत्वाकांक्षी कार्यक्रम की शुरुआत के समय देश के 18.94 करोड़ ग्रामीण घरों में से केवल 3.23 करोड़ (17%) घरों में नल के पानी के कनेक्शन थे। कोविड-19 महामारी और लॉकडाउन व्यवधानों के बावजूद जल जीवन मिशन ने 23 महीनों के दौरान 4.49 करोड़ नल के पानी के कनेक्शन प्रदान किए और 50 हजार ग्राम पंचायतों में हर घर में नल का पानी उपलब्ध कराकर इन पंचायतों में 'हर घर जल' पहुंचाने का लक्ष्य हासिल कर लिया।

इस समय देश के 7.72 करोड़ (40.77%) घरों में नल के पानी की आपूर्ति हो रही है। गोवा, तेलंगाना, अंडमान-निकोबार द्वीप समूह और पुडुच्चेरी ने ग्रामीण क्षेत्रों में 100% घरेलू कनेक्शन का लक्ष्य हासिल कर लिया है और वहां 'हर घर जल' का सपना साकार हो गया है। वर्तमान में देश के 71 जिलों, 824 प्रखंडों, 50,309 ग्राम पंचायतों और 1,00,275 गांवों में 'हर घर जल' का लक्ष्य हासिल कर लिया गया है। ■

विशेष इस्पात (स्पेशियलटी स्टील) के लिए उत्पादन-सम्बद्ध प्रोत्साहन योजना को मिली मंजूरी

गत 22 जुलाई को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विशेष इस्पात के लिए उत्पादन-सम्बद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना को मंजूरी दी। इस योजना की अवधि वर्ष 2023-24 से वर्ष 2027-28 तक पांच वर्षों की होगी। 6322 करोड़ रुपये के बजटीय परिव्यय के साथ इस योजना से करीब 40,000 करोड़ रुपये का निवेश होने और विशेष इस्पात के लिए 25 मिलियन टन क्षमता का संवर्धन होने की उम्मीद है। इस योजना से करीब 5,25,000 लोगों को रोजगार मिलेगा जिसमें से 68,000 प्रत्यक्ष रोजगार होगा।

विशेष इस्पात को लक्ष्य सेग्मेंट के रूप में चुना गया है क्योंकि वर्ष 2020-21 में 102 मिलियन टन इस्पात के उत्पादन में से देश में मूल्य-वर्धित इस्पात/विशेष इस्पात के केवल 18 मिलियन टन का उत्पादन हुआ था। इसके अलावा, उसी वर्ष 6.7 मिलियन टन के आयात में से करीब 4 मिलियन टन आयात विशेष इस्पात का ही था, जिसके परिणामस्वरूप करीब 30,000 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा का व्यय हुआ। विशेष इस्पात के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनकर भारत इस्पात की मूल्य श्रृंखला में उन्नति करेगा और कोरिया और जापान जैसे उन्नत इस्पात विनिर्माणकारी देशों के समकक्ष आएगा।

आशा है कि वर्ष 2026-27 के अंत तक विशेष इस्पात का उत्पादन 42 मिलियन टन हो जाएगा। इससे यह सुनिश्चित होगा कि करीब 2.5 लाख करोड़ मूल्य के विशेष इस्पात का उत्पादन और खपत भारत में होगा जिसका अन्यथा आयात किया जाता। इसी प्रकार, विशेष इस्पात का निर्यात वर्तमान के 1.7 मिलियन टन के मुकाबले लगभग 5.5 मिलियन टन हो जाएगा, जिससे 33,000 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा प्राप्त होगी। इस योजना का लाभ बड़े भागीदारों अर्थात एकीकृत इस्पात संयंत्रों और छोटे भागीदारों (द्वितीय इस्पात भागीदार), दोनों को प्राप्त होगा।

विशेष इस्पात मूल्यवर्धित इस्पात है जिसमें सामान्य तैयार इस्पात को उच्च मूल्यवर्धित इस्पात में परिवर्तित करने के लिए उस पर कोटिंग, प्लेटिंग, हीट-ट्रीटमेंट के जरिये प्रभाव डाला जाता है। जिसका प्रयोग ऑटोमोबाइल क्षेत्र, विशेषीकृत कैपिटल गुड्स इत्यादि के अलावा विभिन्न रणनीतिक अनुप्रयोगों जैसे-कि रक्षा, अंतरिक्ष, ऊर्जा में किया जा सकता है।

विशेष इस्पात की पांच श्रेणियां जिनको पीएलाई योजना में चुना गया है, निम्नलिखित हैं:

- कोटेड/प्लेटेड इस्पात उत्पाद
- हाई स्ट्रेंथ/वियर रेजिस्टेंट स्टील
- स्पेशियलटी रेल
- अलॉय स्टील उत्पाद और स्टील वॉयर
- इलेक्ट्रिकल स्टील

इन उत्पाद श्रेणियों में से आशा है कि इस योजना के पूरा होने के बाद भारत एपीआई ग्रेड पाइप, हेड हार्डेन्ड रेल, इलेक्ट्रिकल स्टील (ट्रांसफार्मर और विद्युत उपकरणों में आवश्यक) जैसे उत्पादों का विनिर्माण करना शुरू कर देगा जिनका फिलहाल बहुत ही सीमित मात्रा में विनिर्माण होता है या बिल्कुल भी विनिर्माण नहीं होता है।

पीएलआई प्रोत्साहन (इन्सेंटिव) के तीन स्लैब हैं, निम्नतम स्लैब 4% और उच्चतम 12% है, जिसका इलेक्ट्रिकल स्टील (सीआरजीओ) के लिए प्रावधान किया गया है। विशेष इस्पात के लिए पीएलआई योजना से यह सुनिश्चित होगा कि प्रयुक्त मूल इस्पात को देश के भीतर पिघलाया और ढाला जाता है। जिसका अर्थ है कि विशेष इस्पात का विनिर्माण करने के लिए प्रयुक्त कच्चा माल (तैयार इस्पात) भारत में ही बनाया जाएगा, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि योजना से देश के भीतर एंड-टू-एंड विनिर्माण को बढ़ावा मिले। ■

पांच चिकित्सा उपकरणों पर ट्रेड मार्जिन 70 फीसदी तक सीमित

कोविड-19 महामारी के बढ़ते मामलों की वजह से चिकित्सा उपकरणों की मांग निरंतर बढ़ रही है, मांग को देखते हुए केंद्र सरकार ने सस्ते स्वास्थ्य देखभाल और कोविड-19 प्रबंधन के लिए उनकी कीमतों को नियमित करने का फैसला लिया है। इसके तहत व्यापक जनहित को देखते हुए राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण एजेंसी (एनपीपीए) ने डीपीसीओ, 2013 के पैरा 19 के तहत मिली असाधारण शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए 13 जुलाई, 2021 को अधिसूचना जारी की। इसके तहत (1) पल्स ऑक्सीमीटर, (2) ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग मशीन, (3) नेब्युलाइज़र, (4) डिजिटल थर्मामीटर और (5) ग्लूकोमीटर की कीमत से लेकर वितरण स्तर पर ट्रेड मार्जिन को अधिकतम 70 फीसदी तक तय कर दिया।

इससे पहले फरवरी, 2019 में एनपीपीए ने कैंसर रोधी दवाओं पर ट्रेड मार्जिन और 3 जून, 2021 को ऑक्सीजन कंसनट्रेटर के लिए ट्रेड मार्जिन की अधिकतम सीमा को तय कर दिया था। अधिसूचित ट्रेड मार्जिन के लिए जारी अधिसूचना के आधार पर एनपीपीए ने निर्माताओं/आयातकों को सात दिनों के भीतर संशोधित एमआरपी को रिपोर्ट करने का निर्देश दिया है। ■

समाज और विचारधारा

दीनदयाल उपाध्याय

हम लोग संगठन के काम में लगे हुए हैं। संगठन शब्द का उच्चारण करते ही जो एक सामान्य कल्पना किसी भी व्यक्ति के सामने आएगी कि उसमें एक से अधिक लोग मिलकर काम करते हैं, अर्थात् यह एक प्रकार का समूहवाचक शब्द है। एक समष्टि है। एक व्यक्ति का प्रश्न नहीं, अनेक को मिलाने का प्रश्न आकर खड़ा हो जाता है। इसलिए व्यक्ति और समष्टि का जो पारस्परिक संबंध है, उसको अच्छी प्रकार समझ लेना चाहिए। क्योंकि इसके बिना स्वयंसेवक के नाते सही व्यवहार संभव नहीं है। इसके द्वारा विश्व के सामने जो जटिल समस्याएं बनी हुई हैं, उनका भी रास्ता निकाला जा सकता है।

मनुष्य के संबंध में प्रारंभ से ही कहा गया कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह अकेला नहीं रह सकता। समाज में रहना उसका गुण है, उसकी प्रकृति है। यह जो उसकी प्रकृतिजन्य बात है, उसको कई बार लोग भूल जाते हैं। वास्तव में, 'मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है', इसका अर्थ यह नहीं और न ही यह लगाना चाहिए। फिर भी कई लोग ये अर्थ लगाते हैं कि समाज मनुष्यों से मिलकर बना है। कारण यह कि मनुष्य दिखाई देता है, समाज दिखाई नहीं देता। समाज एक समूहवाचक सत्ता है, क्योंकि कई चीजों को मिलाकर बना है। इस प्रकार मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इसको समझने में लोगों ने मनुष्य पर अधिक बल दिया है। मनुष्य प्रमुख है और समाज बना है व्यक्ति के लिए, व्यक्ति का भला करने के लिए। व्यक्ति उसे बनाता है, बदलता है तथा बिगाड़ता है। इस प्रकार वे लोग व्यक्ति की स्वतंत्रता को सर्वोपरि मानते हैं। उसको सर्वोपरि समझकर वे सारे कार्यकलापों का विचार करते हैं।

व्यक्ति जब से अपने को केन्द्र बनाकर चलने लगा है तो सामान्यतः वह समाज को भूलने लगा है। कई बार लाभ की चीजों को भी मनुष्य भूल जाता है। प्रकृति का नियम है कि भूख न हो तो भोजन नहीं करना चाहिए। क्या खाना चाहिए, क्या नहीं, यह बात पशुओं को भी मालूम रहती है। यह जहरीली घास है, ऐसा जानवरों को कौन बताने जाता है? ऐसा तो है नहीं कि उसमें विष लिखा रहता है। मनुष्य के लिए जैसे शीशी पर 'विष' या बिजली के खंभे पर 'खतरा' लिखा रहता है, ताकि लोगों को पता लग जाए कि इसमें खतरा है। पशु-पक्षियों को तो कोई बताता नहीं और उस पर लिखा भी नहीं रहता, लेकिन जंगल में चरनेवाली गाय जहरीली घास नहीं खाएगी। जिससे पशु को कोई बीमारी हो तो वह भोजन पशु नहीं खाएगा। लेकिन मनुष्य भूल जाता है। पेट भरा है, फिर भी मीठी प्लेट आ गई तो खा ही लो। कह नहीं सकते कि यह मनुष्य की मूर्खता है या आदत।

लेकिन भगवान ने इसके पेट को लचकदार बना दिया है। सामान्यतः वह खा लेता है। शरीर की प्रकृति से संबंधित वस्तुओं को वह भूल जाता है। वैसे ही समाज के बारे में भी यह भूल जाता है कि यह एक लाभ की वस्तु है। समाज से अलग रहकर वह शायद बोल नहीं पाएगा, जिस बच्चे को भेड़िए उठा ले जाते हैं, वह बोल नहीं पाता। हम यदि दो पांव पर खड़े हैं तो समाज के कारण। एक वैज्ञानिक का तो कहना है कि बुद्धि के विकास का श्रेय दो पांव पर खड़े होनेवाले मनुष्य को ही है। समाज से अलग रहकर वह शायद इस प्रकार बोल नहीं पाएगा। विचारों को तो व्यक्त करने का प्रश्न ही नहीं, भाषा भी वह समाज से सीखता है। अच्छे-बुरे का ज्ञान भी वह समाज से सीखता है। रॉबिन्सन क्रूसो का जहाज एक समुद्र में डूब गया। उसने एक टापू पर आश्रय लिया। उसने वहां मकान बनाया, खेती की, लेकिन उसे 'मैं अकेला हूं' का भाव खटकता रहा। एक बार उसने एक जंगली कैदी को देखा, जिसे वहां के नरभक्षी मनुष्यों ने कैद कर रखा था और वह वहां से भागकर आया था। उस छूटे हुए कैदी को देखकर उसे असीम आनंद हुआ, यद्यपि वह उसकी भाषा तक को नहीं समझता था। उसके भावों को एक कवि ने व्यक्त किया है, जिसका भाव इस प्रकार है, मैं ही स्वामी हूं इस भू प्रदेश पर। इतना सब होने पर भी यहां की शांति मुझे खा रही है। जिस एकांत के बड़े-बड़े ऋषियों ने गान किए, वे आकर्षण कहां हैं? यहां का राज्य भी मुझे स्वीकार नहीं। नरक में रहना आसान है।'

इससे स्पष्ट है कि उसे निर्जनता से कितनी पीड़ा है। अकेले में सभी को भय लगता है। दो रहे तो बल आ जाता है। कहते हैं कि मिट्टी के भी दो पुतले होंगे तो उनमें बल होगा। समाज के कारण आज चाहे कितना भी विकार हुआ है, हमारे सब गुण निर्भयता, आत्मविश्वास आदि का भी विकास समाज के कारण ही है। समाज को निकाल दीजिए धर्म का कोई गुण नहीं रहेगा। धर्म के गुण समाज के कारण ही हैं। दूसरा व्यक्ति ही नहीं तो क्षमा किसको करेंगे? धैर्य की परीक्षा कैसे होगी? रोबिन्सन क्रूसो क्या चोरी करता? अतः यह सब गुण समाज सापेक्ष है। शुचिता भी सामूहिक होती है। धर्म ही समाज के आधार पर खड़ा है।

इतना सब कुछ होने के बाद भी मनुष्य में ये प्रवृत्ति आ जाती है। व्यक्ति—यही सब कुछ है। यह सब मेरे लिए है, यह प्रवृत्ति आई, इसलिए समाज का उपयोग मैं अपने लिए करूं, यह विचार उठने लगा। भगवान का भी यदि विचार करें तो 'भगवान को सब समर्पित कर दूंगा', कहने पर भी अधिकांश यह भावना बनी रहती है कि भगवान यानी मेरे लिए है भगवान। ऐसा कर दो, परीक्षा में पास कर दो, यह दुःख निवारण कर दो, वह कर दो, ऐसी प्रार्थना में समर्पण का भाव नहीं रहता। हम भक्ति करते हैं, इसलिए कि वह हमारा बिना पैसा का बड़ा नौकर है। भगवान का स्मरण भी तब करते हैं जब जरूरत

होती है। ऐसा ही भाव समाज के प्रति हो गया है।

व्यक्ति तथा समाज दोनों एक हैं, यह केंद्र का विचार बिगड़ जाने से समाज के प्रति दुर्लक्ष्य हो गया है। एक ऐसी प्रवृत्ति पैदा हो गई कि व्यक्ति की बुराइयों की बाढ़ आ गई। "Man is a social animal" यह कहने में भी जो मनुष्य को पशु कहा गया, उससे भी एक भाव उत्पन्न हुआ। पशु में भी जो अच्छी चीज दिखाई देती है, उसको न ग्रहण करके 'आहार निद्रा भय मैथुनं च' के सामान्य भाव से सुख ग्रहण करने की कल्पना और पुष्ट हो गई। मनुष्य का अपना सुख सामने आ गया और समाज का विचार सामने से हट गया। स्वार्थ बढ़ गया और दूसरों के अधिकारों का अपहरण प्रारंभ हो गया। दूसरों को अपने सुख के लिए गुलाम तक बनाया गया। पहले 'हमारे लिए' यह भाव था, फिर 'मेरे लिए' यह भाव आया। इस प्रकार दूसरों की ओर दुर्लक्ष्य किया जाने लगा। इस प्रकार दस लोगों को तो खूब खाने को मिलने लगा और इसके कारण वे बीमार होकर मरने लगे और शेष नब्बे लोग भूखे रहकर मरने लगे।

लेकिन आखिर तो मनुष्य में सहानुभूति की भावना भी है। वह सामाजिक प्राणी है। यह विचार आया कि यह प्रकृति के विपरीत है कि दस लोग इसलिए बीमार रहें कि वे अधिक खाएं, दूसरी ओर नब्बे लोग भूख से मरें। यूरोप वालों ने सोचा कि ये जो दस हैं, ये उत्पादन के साधनों के स्वामी हैं, शेष जीविका के लिए इस पर निर्भर करते हैं। इसलिए वे सब के सब एक गुलाम के रूप में हैं। यदि इनके हाथ से स्वामित्व निकाल लिया जाए तो जो पैदावार होगी, उसका बराबर विभाजन होगा। विषमता मिट जाएगी। कुछ लोगों के हाथ में जो सारी धन-संपत्ति सीमित हो गई है, उसको बांट दिया जाना चाहिए। अब प्रश्न रहा कि यह बांटा कैसे जाए और सोचते-सोचते आखिरी रास्ता जिसे दुनिया के लोग समाजवाद के नाम से कहते हैं, कार्ल मार्क्स ने बताया। उसने कहा कि दस लोगों से लेकर किसको दें? तो यह राज्य को दे दिया जाए। क्योंकि समाज तो अव्यक्त चीज है। समाज को दें अर्थात् किसको दें? अतः उन्होंने राज्य को दें, यह नारा लगाया। अगर यह विषमता समाप्त कर समता लानी है, तो इसे राज्य को दे दिया जाए।

जब व्यक्ति का स्वामित्व इन उत्पादनों के साधनों पर हो तो इसे व्यक्तिवाद का नाम दिया गया और समाजवाद इसे अपना विरोधी तथा पूंजीवाद के नाम से मानकर चलता है। पूंजी तो हमारे लिए चाहिए होती है। अतः यह नाम गलत हुआ। छोटे-से-छोटे किसान को भी बीज, हल आदि के रूप में पूंजी चाहिए, जो आर्थिक उत्पादन के सामने माने जाते हैं, श्रम, पूंजी तथा भूमि आदि इन सबसे पूंजी का अस्तित्व है। पूंजी से मतलब पूंजीवाद नहीं लेना चाहिए, जिस प्रकार व्यक्ति से मतलब जातिवाद नहीं होता, संप्रदाय का मतलब संप्रदायवाद नहीं होता, जाति रहने से मतलब जातिवाद नहीं होता। जब ये चीजें विकृत रूप से आकर प्रकट होती हैं और शेष विचार पीछे पड़ जाते हैं तो वाद उत्पन्न होता है— पूंजीवाद, व्यक्तिवाद, संप्रदायवाद आदि।

जब सामान्य जीवन की कल्पनाओं की तिलांजलि देकर, दूसरों की कठिनाई देकर भी केवल पूंजी कमाने की धुन हो, तभी पूंजीवाद कहलाएगा। इसमें केवल मुनाफे का विचार होता है। कोई भी ढंग उसके लिए अपनाना पड़े, वह अपनाता है। पूंजीवाद का जो विरोध आया तो इसी रूप में। उसमें से विषमताएं पैदा हुईं। मनुष्य की सहानुभूति की भावना, चेतना जाग्रत् हुई। इसे घटाना ही चाहिए। बहुत दिनों तक इससे लड़ते रहे। अंत में उत्पादन के साधनों को समाज के हाथों में दे देना चाहिए, यह विचार आया। मार्क्स ने इतिहास का विश्लेषण करके यह बताया कि समाज का इतिहास आर्थिक संघर्ष का इतिहास है। उसने नियम प्रतिपादित किए कि आर्थिक उत्पादन के साधन समाज को दे देने चाहिए। समाज को दे दें अर्थात् किसको दे दें। समाज तो अव्यक्त चीज है। जैसे समाज सेवा कहें तो प्रश्न उठता है किसकी सेवा? मार्क्स ने बताया कि राज्य उसका प्रतिनिधित्व करता है। इस पर राज्यवाद का जन्म हुआ।

उन्होंने सोचा कि इससे समस्या हल हो जाएगी। वे भूल गए कि राज्य चलानेवाले भी व्यक्ति होते हैं। जिस पर सत्ता केंद्रित होती है, वे शोषण नहीं करेंगे, इसकी क्या गारंटी है? व्यक्ति का सामान्य आदर्श दान, क्षमा, दया, आदि जो पूंजीवाद में थे, वह यद्यपि भौतिक आदर्श ही थे परंतु मार्क्स ने उन्हें भी समाप्त कर दिया। इस प्रकार समाज-निष्ठा के समाप्त हो जाने के कारण जो दूसरे के हित के लिए सोचने की भावना थी, वह भी समाप्त होने लगी। वहां प्रचलित संप्रदाय ईसाइयत और इसलाम में भी जो सामान्य पवित्रता है, जैसे दान पद्धति, प्रेम, सेवा, ईमानदारी आदि इनका भी जो भाव समाज में था, अब समाप्त होने लगा। यह सब तो पूंजीवाद की शोषक व्यवस्थाएं हैं, ऐसा बताकर इन सब सामान्य चीजों को भी समाप्त कर दिया गया। इन व्यवस्थाओं के अनुसार जो छह रोटी वाले थे, उन्हें यह बताया जाता था कि यदि दो रोटी दान करोगे तो ये दो रोटी तुम्हें स्वर्ग में मिलेंगी। वह दो रोटी भी उसने दान देनी बंद कर दी और सोचा कि छह की छह रोटी अपने पास ही रख लीं तो कोई बात नहीं।

दूसरी जो नई गलती इस वाद ने की, वह यह थी कि इसने लोगों के सामने भौतिक दृष्टिकोण रखा। इंद्रिय सुख ही ठीक है। यही जीवन का लक्ष्य है। अन्य प्रेरणाएं, जिनमें मन का सुख प्राप्त होता है, जिसके कारण मां स्वयं न खाकर बालक को खिलाती है तथा बुद्धि का सुख व आत्मिक सुख इन सबका विचार उसने नहीं किया। सारे विश्लेषण का आधार भौतिक सुख ही रहा। केवल एक ही प्रेरणा बची है, पर उसका विचार शायद मार्क्स ने तो नहीं किया था। उसने यह तो जरूर कहा था कि समाज के ठेकेदारों से लड़ना पड़ेगा। उनसे लड़ने को कौन तैयार हुए, जिनको केवल दुःख हुआ था। जो मानवीय सहानुभूति से पूर्ण थे ऐसे वर्ग के लोग, जो भूखों को नहीं देख पाते थे, इनकी प्रेरणा भौतिकवादी विश्लेषण के अंतर्गत नहीं आती। जिन्हें सामान्य दुःख हुआ और वह समाज-निष्ठा लेकर खड़े हुए, ऐसे समूह के बलबूते पर एक वर्ग तैयार हुआ, जिसने समाज का विचार किया। समाजवाद में समाज के कल्याण को प्रमुखता थी। ■

(संघ शिक्षा वर्ग, बौद्धिक वर्ग, नई दिल्ली; 18 जून, 1963)

निष्काम कर्मयोगी 'कुशाभाऊ ठाकरे'

(15 अगस्त, 1922 – 28 दिसंबर, 2003)

निष्काम कर्मयोगी श्री कुशाभाऊ ठाकरे नैतिकता, आदर्श व सिद्धांतों के प्रकाशस्तंभ थे। भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी की बुनियाद को मजबूत बनाने में उनका अमूल्य योगदान है। वे जीवनपर्यंत समर्पित रहे। श्री ठाकरे उन नेताओं में से थे, जिन्होंने साइकिल चलाकर और चने खाकर पार्टी का काम किया। यही कारण है कि पार्टी में उनका व्यापक प्रभाव था।

श्री कुशाभाऊ ठाकरे का जन्म 15 अगस्त, 1922 को मध्य प्रदेश स्थित धार में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री सुंदर राव श्रीपति राव ठाकरे और माता का नाम श्रीमती शांता भाई सुंदर राव ठाकरे था। इनकी शिक्षा धार और ग्वालियर में हुई थी। 1942 में संघ का प्रचारक बनने के बाद उन्होंने मध्यप्रदेश के कोने-कोने में निष्ठावान स्वयंसेवकों की सेना खड़ी की। वे कुशल संगठनकर्ता थे।

श्री ठाकरे ने संघ में काम की शुरुआत उस समय की थी, जब इस संगठन का विस्तार व्यापक नहीं था। सच तो यह है कि किसी विचारधारा और लक्ष्य के प्रति उनके समान निष्ठा बिरले लोगों में देखी जाती है। उनके सार्वजनिक जीवन को दो भागों में बांटा जा सकता है। वे प्रारंभ में केवल संघ के काम से जुड़े रहे। जनसंघ (अब भाजपा) की स्थापना के बाद उनका संबंध राजनैतिक गतिविधियों से हुआ। उन्होंने अपने-आपको संगठन तक सीमित रखा और संगठन को और मजबूत बनाने के लिए सदैव कार्य करते रहे।

श्री कुशाभाऊ ठाकरे 1956 में मध्य प्रदेश मंत्री (संगठन) बने। वे 1967 में भारतीय जनसंघ के अखिल भारतीय मंत्री बने। आपातकाल के दौरान वे 19 महीने जेल में रहे। 1980 में भाजपा के अखिल भारतीय मंत्री बनाए गए। 1986 से 1991 तक वे अखिल भारतीय महामंत्री व मध्य प्रदेश के प्रभारी रहे। 1998 में वे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और इस पद वे 2000 तक रहे। उनका देहावसान 28 दिसंबर, 2003 को हुआ।

कुशाभाऊ के प्रेरक विचार

इंदौर में एक सम्मान समारोह में श्री कुशाभाऊ ठाकरे ने कहा कि हमारी सरकार ने तय किया है कि सामने वाले के पास परमाणु बम है, तो हमारा सिपाही तमंचे से नहीं लड़ेगा। हमने अपनी सेना को आधुनिक और आणविक क्षमता से लैस करना जरूरी समझा। हमें पता था कि ऐसा करने पर हमें कमजोर करने का प्रयास किया जाएगा, आर्थिक प्रतिबंध लगाए जाएंगे। उनको लगता है कि ऐसा करने से भारत डूब जाएगा, पर भारत हमेशा ही अपने पैरों पर खड़ा था, खड़ा है और हमेशा खड़ा रहेगा। देश के विकास में लगे 80 प्रतिशत साधन स्वदेशी हैं। विदेशी मदद तो मात्र 15-20 प्रतिशत है। हम सूखी रोटी खा लेंगे, पर पश्चिमी देशों के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे। श्री ठाकरे स्वाभिमान पर समझौता करने वाले व्यक्ति नहीं थे, इसलिए वे राष्ट्र को मजबूत और शक्तिशाली देखना चाहते थे।

श्री ठाकरे का मानना था कि किसी राजनैतिक संगठन का उद्देश्य समाज के हर वर्ग की सुख-समृद्धि सुनिश्चित करना है। 7 फरवरी, 1999 को भोपाल में श्री ठाकरे ने कहा कि भाजपा का लक्ष्य सिर्फ राजनीतिक सफलता पाना नहीं है। पार्टी का मकसद है कि समाज के सभी वर्गों में सुख और समृद्धि आए। आज समाज में दरार चौड़ी करके राजनीतिक कामयाबी तो हासिल की जाती है, पर लोगों के दिलों में घर नहीं बनाया जा सकता। भाजपा वे रास्ते कभी नहीं अपनाएगी जो दूसरे दल अपनाते हैं।

श्री कुशाभाऊ ठाकरे जीवनपर्यंत संगठन के लिए कार्य करते रहे। कार्यकर्ताओं से उनका संबंध अटूट था। 19 अप्रैल, 1996 को भोपाल में उन्होंने कहा था कि हमारी ताकत हमारे कार्यकर्ता हैं। जनता ने हम पर चुनौतीपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है। जनता को वर्तमान सरकार से बहुत आशा है। ऐसे समय में भाजपा कार्यकर्ताओं का दायित्व बढ़ गया है और हमें अपना दायित्व समझना होगा। ■

कोविड स्थिति पर प्रधानमंत्री की 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत

'हमें तीसरी लहर की संभ

गत 16 जुलाई को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, ओडिशा, महाराष्ट्र और केरल के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत करके कोविड की स्थिति पर चर्चा की। बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री भी मौजूद थे। मुख्यमंत्रियों ने प्रधानमंत्री को कोविड से निपटने में हर संभव मदद और समर्थन देने के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री को टीकाकरण की प्रगति और उनके राज्यों में वायरस के फैलाव को रोकने के लिए उठाए जा रहे कदमों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने टीकाकरण रणनीति के बारे में फीडबैक भी दिए।

मुख्यमंत्रियों ने चिकित्सा अवसंरचना को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदमों की चर्चा की और भविष्य में मामलों की किसी भी संभावित वृद्धि से निपटने के बारे में सुझाव दिए। उन्होंने मरीजों के सामने आ रहे कोविड बाद के विषयों तथा ऐसे मामलों में सहायता प्रदान करने के लिए उठाए जा रहे कदमों पर भी चर्चा की। मुख्यमंत्रियों ने आश्वासन दिया कि वे संक्रमण में वृद्धि पर काबू पाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं।

केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि इन छह राज्यों में जुलाई माह के दौरान कुल मामलों का 80 प्रतिशत से अधिक हिस्सा है, जबकि इनमें से कुछ राज्यों में टेस्ट पॉजिटिविटी की दर बहुत अधिक है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने देश में कोविड मामलों पर चर्चा की और हाई केस लोड वाले जिलों में कोविड उपयुक्त व्यवहार और रोकथाम उपायों को मजबूत बनाने की आवश्यकता जताई। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि इन जिलों को खोलने का कार्य क्रमिक रूप से और जांच-परख कर किया जाना चाहिए।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने राज्य सरकारों के आपसी सहयोग और महामारी के खिलाफ उनकी लड़ाई में सीखने के लिए सराहना की। श्री मोदी ने कहा कि हम सभी ऐसे मुकाम पर हैं, जहां तीसरी लहर की आशंकाएं लगातार व्यक्त की जाती हैं। उन्होंने कहा कि मामलों में कमी के कारण विशेषज्ञ सकारात्मक संकेत दे रहे हैं लेकिन कुछ राज्यों में मामलों की बढ़ती संख्या अभी भी चिंताजनक है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने राज्य सरकारों के आपसी सहयोग और महामारी के खिलाफ उनकी लड़ाई में सीखने के लिए सराहना की। श्री मोदी ने कहा कि हम सभी ऐसे मुकाम पर हैं, जहां तीसरी लहर की आशंकाएं लगातार व्यक्त की जाती हैं। मामलों में कमी के कारण विशेषज्ञ सकारात्मक संकेत दे रहे हैं लेकिन कुछ राज्यों में मामलों की बढ़ती संख्या अभी भी चिंताजनक है

केरल और महाराष्ट्र में बढ़ती कोविड संख्या गंभीर चिंता का कारण

श्री मोदी ने बताया कि पिछले सप्ताह के दौरान 80 प्रतिशत मामले और 84 प्रतिशत दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु बैठक में उपस्थित राज्यों में हुईं। प्रारंभ में विशेषज्ञ मान रहे थे कि जिन राज्यों में दूसरी लहर की शुरुआत हुई वहां पहले हालात सामान्य होंगे। उन्होंने कहा कि केरल और महाराष्ट्र में बढ़ती संख्या गंभीर चिंता का कारण है।

श्री मोदी ने आगाह किया कि दूसरी लहर से पहले जनवरी-फरवरी में भी इसी तरह के रुझान देखने को मिले थे। प्रधानमंत्री ने इसी कारण जोर देकर कहा कि जिन राज्यों में मामले बढ़ रहे हैं, वहां हमें तीसरी लहर की संभावना को रोकने के लिए सक्रिय उपाय करने होंगे।

श्री मोदी ने विशेषज्ञ के इस विचार को रेखांकित किया कि अगर मामले लंबे समय तक बढ़ते रहे तो कोरोना वायरस के म्यूटेशन की संभावना भी बढ़ जाएगी और नए वेरिएंट के खतरे भी बढ़ जाएंगे। उन्होंने कहा कि इसीलिए हमें माइक्रो-कंटेनमेंट जोन पर विशेष ध्यान देते हुए टेस्ट, ट्रैक, इलाज और टीका (टीकाकरण) की रणनीति को जारी रखने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या वाले जिलों पर फोकस किया जाना चाहिए।

ावना को रोकने के लिए सक्रिय उपाय करने होंगे'

जांच का काम बढ़ाने पर जोर

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पूरे राज्यों में जांच का काम बढ़ाने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने टीके को उच्च संक्रमण वाले क्षेत्रों के लिए एक रणनीतिक उपाय बताते हुए टीकाकरण के प्रभावी उपयोग पर बल दिया। उन्होंने उन राज्यों की सराहना की जो इस समय का उपयोग अपनी आरटी-पीसीआर जांच क्षमता में सुधार के लिए कर रहे हैं।

श्री मोदी ने आईसीयू बिस्तर और जांच क्षमता जैसी चिकित्सा अवसंरचना बढ़ाने के लिए दी जा रही वित्तीय सहायता की भी चर्चा की। प्रधानमंत्री ने हाल ही में स्वीकृत 23,000 करोड़ रुपये के आपातकालीन कोविड प्रतिक्रिया पैकेज का जिक्र करते हुए राज्यों से कहा कि वे चिकित्सा बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए धन का उपयोग करें।

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने हाल ही में स्वीकृत 23,000 करोड़ रुपये के आपातकालीन कोविड प्रतिक्रिया पैकेज का जिक्र करते हुए राज्यों से कहा कि वे चिकित्सा बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए धन का उपयोग करें

श्री मोदी ने राज्यों से विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में ढांचागत कमियों को दूर करने का आह्वान किया। उन्होंने आईटी सिस्टम, कंट्रोल रूम और कॉल सेंटरों को मजबूत बनाने को भी कहा ताकि पारदर्शी तरीके से संसाधनों और डेटा तक नागरिकों की पहुंच हो सके और मरीजों को परेशानी से बचा जा सके। श्री मोदी ने कहा कि बैठक में उपस्थित राज्यों को आवंटित 332 पीएसए संयंत्रों में से 53 संयंत्र चालू हो चुके हैं। उन्होंने मुख्यमंत्रियों से संयंत्रों को तेजी से पूरा करने को कहा। श्री मोदी ने बच्चों को संक्रमित होने से बचाने और इस संबंध में हर संभव व्यवस्था करने की जरूरत का विशेष रूप से जिक्र किया।

प्रधानमंत्री ने यूरोप, अमेरिका और बांग्लादेश, इंडोनेशिया थाईलैंड और कई अन्य देशों में मामलों की संख्या बढ़ने पर चिंता व्यक्त की। श्री मोदी ने कहा कि इससे हमें और विश्व को सचेत होना चाहिए।

श्री मोदी ने दोहराया कि कोरोना खत्म नहीं हुआ है और लॉकडाउन के बाद आ रही तस्वीरों पर गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने प्रोटोकॉल का पालन करने और भीड़ से बचने की जरूरत पर बल दिया, क्योंकि बैठक में शामिल कई राज्यों में घनी आबादी वाले महानगर हैं। उन्होंने राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों और स्वयंसेवी संगठनों से भी लोगों में जागरूक बनाने का आह्वान किया। ■

बंगाल में 'कानून का राज' नहीं

पश्चिम बंगाल में चुनावों के बाद की स्थिति 'शासक के कानून' की अभिव्यक्ति है, न कि 'कानून के शासन' की, राज्य में चुनाव बाद की हिंसा की जांच कर रहे एनएचआरसी पैनल ने इसे ममता बनर्जी सरकार के लिए एक घातक कलंक कहा और बलात्कार एवं हत्या के मामलों की जांच सीबीआई से करवाने की सिफारिश की।

कलकत्ता उच्च न्यायालय के पांच न्यायाधीशों की पीठ के आदेश के बाद गठित एनएचआरसी पैनल ने यह भी कहा कि सभी बलात्कार और हत्या के मामलों की सुनवाई राज्य के बाहर की जानी चाहिए। बिजनेस स्टैंडर्ड ने एक समाचार रिपोर्ट में कहा कि समिति ने सिफारिश की है कि हत्या, बलात्कार आदि जैसे गंभीर

अपराधों को जांच के लिए सीबीआई को सौंप दिया जाना चाहिए और इन मामलों में राज्य के बाहर मुकदमा चलाया जाना चाहिए। 13 जून को सीलबंद लिफाफे में यह रिपोर्ट अदालत को सौंपी गई।

सात सदस्यीय समिति की रिपोर्ट में कहा गया है कि पश्चिम बंगाल राज्य की स्थिति 'कानून के शासन' के बजाय 'शासक के कानून' की अभिव्यक्ति करती है।

13 जुलाई को रिपोर्ट पेश किए जाने के बाद अदालत ने निर्देश दिया था कि इसकी सॉफ्ट कॉपी याचिकाकर्ताओं, चुनाव आयोग और भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के वकील को संलग्नक के साथ प्रदान की जाए।

अदालत के समक्ष दायर जनहित याचिकाओं में आरोप लगाया गया था कि चुनाव बाद की हिंसा में लोगों के साथ मारपीट की गई, उन्हें अपने घरों से भागने के लिए मजबूर किया गया और उनकी संपत्ति को नष्ट कर दिया गया।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की पीठ ने कई दिनों तक चली हिंसा के दौरान कथित मानवाधिकार उल्लंघन के सभी मामलों की जांच के लिए 18 जून को एनएचआरसी अध्यक्ष को एक समिति गठित करने का निर्देश दिया था।

एनएचआरसी पैनल ने रिपोर्ट में कहा कि यह सत्तारूढ़ दल के समर्थकों द्वारा मुख्य विपक्षी दल के समर्थकों के खिलाफ प्रतिशोधात्मक हिंसा थी।

वास्तव में यह विडंबना है कि रवींद्र नाथ टैगोर की भूमि में 'जहां, मन हो भय से मुक्त और सिर फक्र से ऊंचा; जहां ज्ञान हो आजाद, जहां दुनिया संकीर्ण सोच से न हो टूटी-बिखरी; वहां पिछले कुछ महीनों में इसके हजारों नागरिकों को हत्या, बलात्कार, विस्थापन और डराने-धमकाने जैसे मामलों का शिकार होना पड़ा है।

रिपोर्ट में पार्टी के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए सरकारी तंत्र के इस्तेमाल की बात भी कही गई है।

"यह इस महान राष्ट्र में लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी हो सकती है। यह सही समय है कि इस नफरत को रोका जाए और इस देश में एक जीवंत लोकतंत्र के पक्ष में इस प्रवृत्ति को बदला जाय," समिति ने जोरदार तरीके से 50 पृष्ठ की रिपोर्ट में यह सब बातें कहीं।

इसमें चेतावनी देते हुए कहा गया है कि यदि इस चिंताजनक प्रवृत्ति की जांच नहीं की गई तो 'बीमारी' अन्य राज्यों में भी फैल सकती है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि हिंसा के कृत्यों से हजारों लोगों के जीवन और आजीविका में बाधा उत्पन्न हुई और उनका आर्थिक नुकसान हुआ। रिपोर्ट में कहा गया है कि स्थानीय पुलिस इस हिंसा में यदि शामिल नहीं तो काफी निष्क्रिय बनी रही।

यह मानते हुए कि हिंसा और धमकी दिये जाने के प्रकरण जारी

हैं, रिपोर्ट में कहा गया है कि पीड़ितों में पुलिस और सत्ताधारी पार्टी के गुंडों के खिलाफ डर है।

इसमें कहा गया है कि कई विस्थापित व्यक्ति अभी तक अपने घरों को नहीं लौट पाए हैं और अपना सामान्य जीवन और आजीविका फिर से शुरू नहीं कर पाए हैं।

रिपोर्ट में कहा गया है कि कई यौन अपराध हुए हैं लेकिन पीड़ित इसके खिलाफ बोलने से डर रहे हैं। पीड़ितों के बीच राज्य प्रशासन में विश्वास की कमी बहुत स्पष्ट है।

पैनल ने कहा कि न तो वरिष्ठ अधिकारियों और न ही राजनीतिक नेताओं ने हिंसा की निंदा की, न घटनास्थल का दौरा किया, न पीड़ितों को आश्वस्त किया या स्थिति को सुधारने के लिए कुछ भी नहीं किया।

समिति ने कहा कि लोगों को उनके मानवीय और मौलिक अधिकारों के उल्लंघन से सुरक्षा के लिए अपने हाल पर छोड़ दिया गया, जिसमें जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता, सम्मानजनक जीवन और स्वास्थ्य शामिल है, क्योंकि यह हिंसा एक खतरनाक राजनीतिक-नौकरशाही-आपराधिक गठजोड़ का परिणाम थी।

सात सदस्यीय पैनल ने उच्च न्यायालय के आदेशों के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक समिति गठित करने की सिफारिश की। समिति में प्रत्येक प्रभावित जिले में पर्यवेक्षक के रूप में स्वतंत्र अधिकारी होने चाहिए।

इसने सुझाव दिया कि बलात्कार और हत्या जैसे गंभीर मामलों को छोड़कर, जिन्हें सीबीआई को सौंप दिया जाना चाहिए, अन्य की जांच अदालत की निगरानी वाली एसआईटी द्वारा की जानी चाहिए। इसमें कहा गया है कि सुनवाई फास्ट ट्रैक अदालतों में होनी चाहिए और गवाहों को पर्याप्त सुरक्षा दी जानी चाहिए।

सिफारिशों में अनुग्रह राशि का भुगतान, संपत्ति के नुकसान के लिए मुआवजा, पीड़ितों का पुनर्वास, महिलाओं की सुरक्षा, केंद्रीय बलों की तैनाती और अपराधी सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की बात शामिल थी।

एनएचआरसी रिपोर्ट की मुख्य बातें:

- पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद की स्थिति "शासक के कानून" की अभिव्यक्ति है, न कि "कानून के शासन" की।
- जांच कर रहे एनएचआरसी पैनल ने इसे ममता बनर्जी सरकार के लिए एक घातक कलंक कहा और रेप और हत्या के मामलों की जांच सीबीआई से करवाने की सिफारिश की।
- समिति ने सिफारिश की है कि हत्या, बलात्कार आदि जैसे गंभीर अपराधों को जांच के लिए सीबीआई को सौंप दिया जाना चाहिए और इन मामलों को राज्य के बाहर चलाया जाना चाहिए।
- यह सत्तारूढ़ दल के समर्थकों द्वारा मुख्य विपक्षी दल के समर्थकों के खिलाफ प्रतिशोधात्मक हिंसा थी।
- पिछले कुछ महीनों में इसके हजारों नागरिकों को हत्या, बलात्कार, विस्थापन और डराने-धमकाने जैसे मामलों का शिकार होना पड़ा है।
- रिपोर्ट में पार्टी के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए सरकारी तंत्र के इस्तेमाल की बात भी कही गई है।
- रिपोर्ट में कहा गया है, "स्थानीय पुलिस इस हिंसा में यदि शामिल नहीं तो काफी निष्क्रिय बनी रही।"
- कई यौन अपराध हुए हैं लेकिन पीड़ित बोलने से डरते हैं।
- इसने सुझाव दिया कि बलात्कार और हत्या जैसे गंभीर मामलों को छोड़कर, जिन्हें सीबीआई को सौंप दिया जाना चाहिए, अन्य की जांच अदालत की निगरानी वाली एसआईटी द्वारा की जानी चाहिए।
- सिफारिशों में अनुग्रह राशि का भुगतान, संपत्ति के नुकसान के लिए मुआवजा, पीड़ितों का पुनर्वास, महिलाओं की सुरक्षा, केंद्रीय बलों की तैनाती और अपराधी सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की बात शामिल थी।

रिपोर्ट तैयार करने से पहले राजीव जैन की अध्यक्षता वाली सात सदस्यीय समिति सहित कई टीमों ने 20 दिनों में राज्य भर में 311 स्थानों का दौरा किया।

पैनल को एनएचआरसी, पश्चिम बंगाल कानूनी सेवा प्राधिकरण, डब्ल्यूबी मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग और अदालतों में दायर याचिकाओं सहित विभिन्न स्रोतों से 15,000 से अधिक पीड़ितों के बारे में लगभग 1,979 शिकायतें मिलीं। ■

भारत की 21वीं सदी की जरूरतें 20वीं सदी के तरीकों से पूरी नहीं की जा सकतीं: नरेन्द्र मोदी

नए भारत के विकास का वाहन एक साथ दो पटरियों पर चलकर ही आगे बढ़ेगा। एक पटरी आधुनिकता की है, दूसरी गरीब, किसानों और मध्यम वर्ग के कल्याण की है

गत 16 जुलाई को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से गुजरात में रेलवे की कई प्रमुख परियोजनाओं का उद्घाटन किया और कई अन्य परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने गुजरात साइंस सिटी में एक्वेटिक्स व रोबोटिक्स गैलरी और नेचर पार्क का भी उद्घाटन किया। उन्होंने दो नई ट्रेनों- गांधीनगर कैपिटल वाराणसी सुपरफास्ट एक्सप्रेस तथा गांधीनगर कैपिटल और वरेथा के बीच मेमू सर्विस ट्रेन- को भी झंडी दिखाकर रवाना किया।

उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि आज देश का लक्ष्य न सिर्फ एक ठोस ढांचा तैयार करना है, बल्कि ऐसा इन्फ्रॉस्ट्रक्चर तैयार करना है जिसका अपना चरित्र हो। उन्होंने कहा कि बच्चों के प्राकृतिक विकास के लिए उनके मनोरंजन के साथ उनकी शिक्षा और रचनात्मकता को भी जगह मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि साइंस सिटी एक ऐसी परियोजना है, जो मनोरंजन और रचनात्मकता का संयोजन है। इसमें मनोरंजन की ऐसी गतिविधियां हैं जो बच्चों में रचनात्मकता को प्रोत्साहन देती हैं।

श्री मोदी ने कहा कि साइंस सिटी में बनी एक्वेटिक्स गैलरी और भी मनोरंजक होने वाली है। यह न केवल देश में बल्कि एशिया में भी सबसे बड़ी एक्वैरियम में से एक है। उन्होंने कहा कि दुनिया भर की समुद्री जैव विविधता का एक ही स्थान पर नजारा अपने आप में एक अद्भुत अनुभव है। उन्होंने कहा कि रोबोटिक्स गैलरी में रोबोट के साथ बातचीत न केवल आकर्षण का केंद्र है, बल्कि हमारे युवाओं को रोबोटिक्स के क्षेत्र में काम करने के लिए प्रेरित भी करेगी और उनके मन में जिज्ञासा उत्पन्न करेगी।

श्री मोदी ने जोर देकर कहा कि भारत की 21वीं सदी की जरूरतों को 20वीं सदी के तौर-तरीकों से पूरा नहीं, किया जा सकता है। इसलिए रेलवे में नए सिरे से सुधार की जरूरत थी। उन्होंने कहा कि आज रेलवे को सिर्फ एक सेवा के रूप में नहीं बल्कि एक संपत्ति के रूप में विकसित करने के प्रयासों के परिणाम दिखाई दे रहे हैं।

देश भर के प्रमुख रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण

नए भारत के विकास का वाहन एक साथ दो पटरियों पर चलकर ही आगे बढ़ेगा। एक पटरी आधुनिकता की है, दूसरी गरीब, किसानों और मध्यम वर्ग के कल्याण की है

श्री मोदी ने कहा कि आज देशभर के प्रमुख रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। यहां तक कि टियर 2 और टियर 3 शहरों के रेलवे स्टेशन भी अब वाई-फाई सुविधाओं से लैस हैं। लोगों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए ब्रॉड गेज पर मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है।

प्रधानमंत्री ने भारत जैसे विशाल देश में रेलवे द्वारा निभाई गई अहम भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि रेलवे विकास और सुविधाओं के नए आयाम लेकर आता है। बीते कुछ साल के दौरान किए गए प्रयासों के कारण आज ट्रेनें पहली बार पूर्वोत्तर की राजधानियों में पहुंच रही हैं।

श्री मोदी ने कहा कि आज वडनगर भी इस विस्तार का अंग बन गया है। वडनगर स्टेशन के साथ मेरी कई यादें जुड़ी हुई हैं। नया स्टेशन वास्तव में काफी आकर्षक दिखता है। इस नई ब्रॉड गेज लाइन के निर्माण के साथ, वडनगर-मोढेरा-पाटन हेरिटेज सर्किट बेहतर रेल सेवा से जुड़ गया है।

उन्होंने कहा कि नए भारत के विकास का वाहन एक साथ दो पटरियों पर चलकर ही आगे बढ़ेगा। एक पटरी आधुनिकता की है, दूसरी गरीब, किसानों और मध्यम वर्ग के कल्याण की है। ■

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल एवं मुख्तार अब्बास नकवी बने राज्यसभा में सदन के नेता एवं उपनेता

केन्द्रीय मंत्री श्री पीयूष गोयल 14 जुलाई को राज्यसभा में सदन के नेता नियुक्त किए गए। श्री गोयल, राज्यसभा में सदन के नेता के तौर पर श्री थावरचंद गहलोत की जगह लेंगे, जो अब कर्नाटक के राज्यपाल हैं। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री श्री प्रल्हाद जोशी ने नियुक्ति की घोषणा करते हुए ट्वीट किया, "पीयूष गोयल जी को राज्यसभा में सदन का नेता नियुक्त किए जाने पर बधाई। उन्हें पीएम नरेन्द्र मोदी जी ने अहम जिम्मेदारी सौंपी है। कामना है कि वह राष्ट्र की सेवा में निरंतर जोश के साथ काम करेंगे।"

57 वर्षीय श्री पीयूष गोयल 2010 से राज्यसभा के सदस्य हैं। उनके पास केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग, खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों और कपड़ा समेत विभिन्न मंत्रालयों का प्रभार है। 2014 में केंद्रीय मंत्री बनने से पहले वे पार्टी के कोषाध्यक्ष थे। चार्टर्ड अकाउंटेंट की परीक्षा में उन्होंने देशभर में दूसरी रैंक हासिल की थी। वह एक बैंकर भी रहे हैं और भारतीय स्टेट बैंक और बैंक आफ बड़ौदा के बोर्ड में रह चुके हैं। जब श्री थावरचंद गहलोत सदन के नेता थे, तब श्री पीयूष गोयल राज्यसभा के उपनेता रह चुके हैं।

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने ट्वीट कर अपने बधाई संदेश में कहा, "मैं राज्यसभा में सदन के नेता नियुक्त होने पर पीयूष गोयल जी को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मुझे विश्वास है कि अपने समृद्ध अनुभव और स्टेट्समैनशिप से आप उच्च सदन में भाजपा की मजबूत आवाज बनेंगे।"

वहीं, केंद्रीय मंत्री श्री मुख्तार अब्बास नकवी को 19 जुलाई को राज्यसभा का उपनेता नियुक्त किया गया। संसदीय कार्य मंत्री श्री

प्रल्हाद जोशी ने राज्यसभा के सभापति श्री एम. वेंकैया नायडू को पत्र लिखकर राज्यसभा के उपनेता के रूप में श्री नकवी की नियुक्ति के बारे में सूचित किया। इस पत्र में श्री जोशी ने कहा, 'प्रधानमंत्री (श्री नरेन्द्र मोदी) ने यह सूचना देने के लिए मुझे निर्देशित किया है कि अल्पसंख्यक कार्य मंत्री श्री मुख्तार अब्बास नकवी को राज्यसभा में उप नेता नियुक्त किया गया है।' इससे पहले उच्च सदन में उप नेता की जिम्मेदारी केंद्रीय मंत्री श्री पीयूष गोयल के पास थी जिन्हें पिछले दिनों राज्यसभा का नया नेता नियुक्त किया गया है।

श्री नकवी पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्ववाली राजग सरकार में भी मंत्री रह चुके हैं। वह कई वर्षों से राज्यसभा के सदस्य हैं और लोकसभा में उत्तर प्रदेश के रामपुर का प्रतिनिधित्व भी कर चुके हैं। वह मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में संसदीय कार्य राज्य मंत्री भी थे। ■

'धारा 370 एवं 35ए हटने से जम्मू-कश्मीर की महिलाओं को लाभ'

भारतीय जनता पार्टी, महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती वानती श्रीनिवासन 10 जुलाई को एक दिवसीय जम्मू-कश्मीर की कार्यकारिणी बैठक में शामिल होने के लिए जम्मू-कश्मीर प्रवास पर रहीं। इस दौरान उन्होंने जम्मू कश्मीर की सभी महिला कार्यकर्ताओं को सम्बोधित किया। उन्होंने धारा 370 और 35ए जम्मू कश्मीर से हटाने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का धन्यवाद किया, क्योंकि जम्मू-कश्मीर की महिलाओं को इसका विशेष लाभ मिला है। यह धारा हटने के बाद अब जम्मू-कश्मीर की महिलाएं जम्मू-कश्मीर से भी बाहर शादी करती हैं तो भी उनको अपने पैतृक सम्पत्ति में अधिकार रहेगा और इसके साथ ही श्रीमती वानती ने कहा कि आज डीडीसी और बीडीसी चुनाव में महिलाओं को मजबूत भागीदारी मिल रही हैं क्योंकि 370 और 35ए हटने के बाद 33 प्रतिशत रिजेंवेशन महिलाओं को मिला। जिसके परिणामस्वरूप इन चुनावों में उनकी एक अच्छी भागीदारी देखने को मिली।

इस कार्यक्रम में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष श्री रविन्द्र रैना, महिला मोर्चा की राष्ट्रीय महामंत्री श्रीमती दीप्ती रावत, भाजपा प्रदेश संगठन महामंत्री श्री अशोक कौल विशेष रूप से उपस्थित रहे। ■

नयी मोदी कैबिनेट 2.0: सामाजिक रूप से सबसे विविध और समावेशी

राम प्रसाद त्रिपाठी

मई, 2019 में अपने दूसरे कार्यकाल का पदभार संभालने के बाद प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पहला कैबिनेट विस्तार किया है, जिसे 'नए भारत' के सपने को साकार करने वाला और देश के संसदीय इतिहास में सामाजिक रूप से सबसे विविध और समावेशी विस्तार माना जा रहा है। इस बदलाव के साथ ही प्रधानमंत्री ने कैबिनेट में जहां एक ओर युवा शक्ति को स्थान दिया है, वहीं दूसरी ओर विभिन्न सामाजिक वर्गों एवं क्षेत्रों के लोगों को शासन में प्रतिनिधित्व दिया है, जो पूरे भारत की विविधता का प्रतिनिधित्व करते हैं।

मंत्रिपरिषद में 43 नए चेहरों को शामिल किया गया है, जिनमें से 15 ने कैबिनेट मंत्री के रूप में और 28 ने राज्य मंत्री के रूप में शपथ ली, केंद्रीय मंत्रिमंडल की कुल संख्या बढ़कर 78 हो गई, जिसमें प्रधानमंत्री भी शामिल हैं।

नयी मोदी कैबिनेट 2.0 में भारत के विभिन्न समुदायों और क्षेत्रों की जीवंतता और रंग शामिल हैं और इस कैबिनेट का प्रतिनिधित्व समाज के लगभग सभी वर्गों द्वारा किया जा रहा है। इसलिए, यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि यह नया मंत्रिमंडल भारत की विविधता का एक सच्चा प्रतिबिंब है जो भारत के गरीबों, सामाजिक रूप से वंचित और पिछड़ों, विभिन्न राज्यों और क्षेत्रों, महिलाओं और युवाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करता है।

इस कैबिनेट का प्रतिनिधित्व समाज के लगभग सभी वर्गों द्वारा किया जा रहा है। इसलिए, यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि यह नया मंत्रिमंडल भारत की विविधता का एक सच्चा प्रतिबिंब है जो भारत के गरीबों, सामाजिक रूप से वंचित और पिछड़ों, विभिन्न राज्यों और क्षेत्रों, महिलाओं और युवाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करता है

विस्तार के बाद मोदी मंत्रिमंडल 2.0 कई मामलों में 'नवीन पहल' करने वाला साबित हुआ है। कैबिनेट में युवा शक्ति को सक्रिय प्रतिनिधित्व दिया गया है। निवर्तमान मंत्रिमंडल में मंत्रियों की औसत आयु 61 वर्ष थी, जबकि नए मंत्रिमंडल में औसत आयु 58 वर्ष है, जिसमें से छह कैबिनेट मंत्रियों सहित 14 मंत्रियों की आयु 50 वर्ष से कम है।

इसी तरह विभिन्न क्षेत्रों की उत्कृष्ट प्रतिभाओं और विशेषज्ञों को भी स्थान दिया गया है जिसमें 13 वकील, छह डॉक्टर, पांच इंजीनियर, सात पूर्व सिविल सेवक, सात पीएचडी और तीन एमबीए शामिल हैं, इसमें 68 से अधिक मंत्री स्नातक हैं।

किसी देश को सशक्त बनाने के लिए महिलाओं का सशक्तिकरण बेहद जरूरी है। इस तथ्य को स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री श्री मोदी ने पिछले सात वर्षों में यह सुनिश्चित किया है कि महिलाओं को पर्याप्त सम्मान एवं भरपूर अवसर मिले। महिलाओं के कल्याण के लिए किए गए जबरदस्त कार्यों को देखते हुए यह दौर निस्संदेह भारत के हाल के इतिहास में 'नारी सशक्तिकरण' के लिए सबसे महत्वपूर्ण समय के रूप में याद किया जाएगा। इसी प्रयास को जारी रखते हुए और नए भारत की विकास गाथा को आकार देते हुए स्वतंत्र भारत में शायद यह पहली बार हुआ है कि जब प्रधानमंत्री ने दो कैबिनेट मंत्रियों सहित 7 महिला मंत्रियों को शामिल किया, अब महिला मंत्रियों की कुल संख्या 11 हो गई है। यह बदलाव दर्शाता है कि यह दौर महिलाओं विकास की अवधारणा से आगे बढ़कर 'महिला नेतृत्व वाले विकास' की ओर चल पड़ा है।

सामाजिक न्याय के संदर्भ में केंद्रीय मंत्रिमंडल में हाल के बदलावों के दूरगामी प्रभाव पड़ने वाले हैं। स्वतंत्र भारत में पहली बार मोदी सरकार 2.0 में आठ राज्यों- बिहार, एमपी, यूपी, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, राजस्थान और तमिलनाडु से दो कैबिनेट मंत्रियों सहित रिकॉर्ड 12 अनुसूचित जाति के मंत्री बने हैं, जो चमार, रामदसिया, खटीक, पासी, कोरी, मडिगा, महार, अरुंधथियार, मेघवाल, राजबंशी, मटुआ-नमाशूद्र, धंगा और दुसाध सहित 12 अनुसूचित जाति समुदायों का प्रतिनिधित्व करते हैं।

इसी तरह मोदी कैबिनेट में रिकॉर्ड आठ एसटी मंत्री हैं और वे आठ राज्यों-अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और असम का प्रतिनिधित्व करते हैं। 3 कैबिनेट मंत्रियों सहित ये आठ एसटी मंत्री सात एसटी समुदायों-गोंड, संताल, मिजी, मुंडा, चाय जनजाति, कोकाना और सोनोवाल-कछारी से आते हैं।

इसी तरह पहली बार 15 राज्यों और 20 समुदायों- यादव, कुर्मी, जाट, गुर्जर, खांडयात, भंडारी, बैरागी, चाय जनजाति, ठाकोर, कोली, वोक्कालिगा तुलु गौड़ा के पांच कैबिनेट मंत्रियों सहित रिकॉर्ड 28 ओबीसी मंत्रियों को शामिल किया गया है। एझावा, लोध, एग्री, वंजारी, मैतेई, नट, मल्लाह-निषाद, मोध तेली और दारज़ी जैसे कई समुदायों को पहली बार कैबिनेट में शामिल किया गया है।

पांच राज्यों-उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, पंजाब और अरुणाचल प्रदेश के पांच अल्पसंख्यक मंत्रियों के साथ अल्पसंख्यकों

को पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिला है। सरकार में तीन कैबिनेट मंत्रियों समेत एक मुस्लिम, एक सिख, एक ईसाई, दो बौद्ध मोदी सरकार का हिस्सा है, जिसका मूल मंत्र 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास' है।

इसके अलावा 29 मंत्री ब्राह्मण, क्षत्रिय, बनिया, भूमिहार, कायस्थ, लिंगायत, खत्री, कदवा एवं लेउवा पटेल, मराठा, रेड्डी और नायर आदि समुदायों से हैं।

मोदी सरकार में वरिष्ठ और अनुभवी प्रशासकों और विधायकों को स्थान दिया गया है, जिसमें 46 मंत्रियों को केंद्र सरकार में मंत्री होने का पूर्व अनुभव है और 23 मंत्रियों को तीन या अधिक कार्यकाल यानी एक दशक का संसदीय अनुभव है ।

कैबिनेट में नए चेहरों को शामिल करने से निस्संदेह सरकार में नई ऊर्जा, गतिशीलता और दृढ़ संकल्प का संचार हुआ है। यह कहने की जरूरत नहीं है कि नई सरकार भारत के विश्व शक्ति के रूप में उभरने के रास्ते में आने वाली किसी भी चुनौती का मुकाबला करने के लिए आत्मविश्वास से भरी है

इसी तरह संघवाद की भावना का सम्मान करते हुए मोदी सरकार ने पहली बार लगभग सभी राज्यों से सांसदों को अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया है। वर्तमान सरकार में 25 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मंत्री हैं। राज्य विधायी अनुभव के साथ पांच पूर्व सीएम, 23 पूर्व मंत्री (राज्य सरकार) और 38 पूर्व विधायक निश्चित रूप से अपने लंबे अनुभव के साथ केंद्र सरकार को समृद्ध करेंगे।

कैबिनेट में नए चेहरों को शामिल करने से निस्संदेह सरकार में नई ऊर्जा, गतिशीलता और दृढ़ संकल्प का संचार हुआ है। यह कहने की जरूरत नहीं है कि नई सरकार भारत के विश्व शक्ति के रूप में उभरने के रास्ते में आने वाली किसी भी चुनौती का मुकाबला करने के लिए आत्मविश्वास से भरी है।

'नए भारत' के इस नए मंत्रिमंडल में देश के सभी राज्यों और क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व मिला है जो पूरे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने एक स्पष्ट संदेश दिया है कि सामाजिक न्याय और लैंगिक न्याय अब प्रतीकात्मक या औपचारिक बातें नहीं है बल्कि महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले पदों पर एक अधिक मजबूत और परिणाम-उन्मुख प्रतिनिधित्व है, जो महत्वपूर्ण बदलाव लाने में हमें सक्षम बनाता है। इसलिए, एससी, एसटी, ओबीसी और महिलाओं को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने के साथ ही यह देश के राजनीतिक इतिहास में सबसे अधिक सामाजिक रूप से विविध और समावेशी मंत्रियों की परिषद् होगी।

हमारे समाज के कमजोर वर्गों को निर्णय लेने वाले और राष्ट्र के मामलों में हितधारक बनाकर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने राष्ट्र के संस्थापकों के सपने को साकार करने और इन वर्गों के समग्र विकास के लिए एक ताज़ा और ऐतिहासिक बदलाव की शुरुआत की है। ■

स्वच्छता और 'मां गंगा' तथा काशी की सुंदरता एक आकांक्षा और प्राथमिकता है: नरेन्द्र मोदी

गत 15 जुलाई को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने वाराणसी में विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (बीएचयू) में 100 बेड की एमसीएच विंग, गोदौलिया में मल्टीलेवल पार्किंग, गंगा नदी में पर्यटन विकास के लिए रो-रो जहाज और वाराणसी गाजीपुर राजमार्ग पर श्री लेन फ्लाईओवर ब्रिज सहित विभिन्न सार्वजनिक परियोजनाओं और कार्यों का उद्घाटन किया।

उन्होंने लगभग 839 करोड़ रुपये की कई परियोजनाओं और लोक निर्माणों का शिलान्यास भी किया। इनमें सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (सीआईपेट) के सेंटर फॉर स्किल एंड टेक्निकल सपोर्ट, जल जीवन मिशन के तहत 143 ग्रामीण परियोजनाएं और करखियांव में आम और सब्जी इंटीग्रेटेड पैक हाउस शामिल हैं।

सभा को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने पिछले कुछ महीनों में उन कठिन दिनों को याद किया जब म्यूटेटेड कोरोना वायरस ने पूरी ताकत से हमला किया। उन्होंने इस चुनौती से निपटने में उत्तर प्रदेश और काशी के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने महामारी से निपटने में उत्तर प्रदेश सरकार के प्रयासों की प्रशंसा की। श्री मोदी ने काशी की अपनी टीम, प्रशासन तथा कोरोना योद्धाओं की टीम की प्रशंसा की, जिन्होंने प्रबंधन करने में दिन-रात एक कर दिए।

उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक संख्या में जांच और टीकाकरण

श्री मोदी ने कहा कि कठिन दिनों में भी काशी ने यह दिखाया है कि वह कभी ठहरती नहीं, कभी थकती नहीं। उन्होंने दूसरी लहर से अभूतपूर्व तरीके से निपटने की तुलना पहले के उदाहरणों से की, जब जापानी इंसेफेलाइटिस तरह की बीमारियां कहर बरपा करती थीं। श्री मोदी ने कहा कि चिकित्सा सुविधाओं और राजनीतिक इच्छाशक्ति के अभाव में छोटी चुनौतियां भी बड़ा स्वरूप ले लेती थीं। उन्होंने कहा कि आज उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक संख्या में जांच और टीकाकरण हुआ है।

श्री मोदी ने उत्तर प्रदेश में चिकित्सा बुनियादी ढांचे में तेजी से हो रहे सुधारों को गिनाया। पिछले चार साल में मेडिकल कॉलेजों की संख्या चार गुना बढ़ी है। कई मेडिकल कॉलेज पूरा होने के विभिन्न चरणों में हैं। उन्होंने राज्य में स्थापित किए जा रहे लगभग 550 ऑक्सीजन संयंत्रों की चर्चा की, जिनमें से 14 का उद्घाटन आज किया गया।

पूर्वांचल का बड़ा मेडिकल हब 'काशी'

श्री मोदी ने राज्य सरकार द्वारा बाल चिकित्सा आइसीयू और ऑक्सीजन सुविधाओं में सुधार के प्रयासों की भी प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि हाल ही में घोषित 23,000 करोड़ रुपये के पैकेज से उत्तर प्रदेश को मदद मिलेगी। श्री मोदी ने कहा कि काशी नगरी पूर्वांचल का बड़ा मेडिकल हब बनता जा रहा है।

उन्होंने कहा कि कुछ बीमारियों का इलाज, जिसके लिए किसी को दिल्ली और मुंबई जाना पड़ता था, अब काशी में उपलब्ध है। श्री मोदी ने कहा कि आज जिन परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया उनसे शहर के चिकित्सा बुनियादी ढांचे में और मजबूती आएगी।

प्रधानमंत्री ने कहा कि कई परियोजनाएं प्राचीन शहर काशी के

मूल तत्व को सुरक्षित रखते हुए विकास के पथ पर अग्रसर हो रही हैं। उन्होंने कहा कि राजमार्ग, फ्लाईओवर, रेलवे ओवरब्रिज, भूमिगत वायरिंग, सीवर और पेयजल की समस्याओं का समाधान, पर्यटन को बढ़ावा देने जैसी परियोजनाओं को सरकार की ओर से अभूतपूर्व तरीके से आगे बढ़ाया गया है। श्री मोदी ने बताया कि वर्तमान में भी 8,000 करोड़ रुपये की योजनाओं पर काम चल रहा है।

उन्होंने कहा कि स्वच्छता और गंगा तथा काशी की सुंदरता ही आकांक्षा और प्राथमिकता है। इसके लिए हर मोर्चे पर सड़क, सीवेज ट्रीटमेंट, पार्कों और घाटों के सौंदर्यीकरण जैसे काम किए जा रहे हैं। पंचकोसी मार्ग को चौड़ा किए जाने, वाराणसी गाजीपुर पर पुल बनने से कई गांवों और आसपास के शहरों को मदद मिलेगी।

श्री मोदी ने कहा कि पूरे शहर में बड़े एलईडी स्क्रीन लगाए गए हैं और घाटों पर नवीनतम प्रौद्योगिकी सूचना बोर्ड काशी आने वाले आगंतुकों के लिए काफी सहायक साबित होंगे। उन्होंने कहा कि ये एलईडी स्क्रीन और सूचना बोर्ड काशी के इतिहास, वास्तुकला, शिल्प, कला, ऐसी हर जानकारी को आकर्षक तरीके से पेश करेंगे और श्रद्धालुओं के लिए काफी काम आएंगे।

प्रधानमंत्री ने कहा कि मां गंगा के घाट और काशी विश्वनाथ मंदिर में आरती का प्रसारण बड़े पर्दे के माध्यम से पूरे शहर में संभव होगा। श्री मोदी ने यह भी बताया कि आज उद्घाटन किए गए रो-रो सेवा और क्रूज सेवा से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि रुद्राक्ष केंद्र, जिसका आज उद्घाटन किया जा रहा है, शहर के कलाकारों को एक विश्व स्तरीय मंच प्रदान करेगा।

श्री मोदी ने आधुनिक समय में काशी के विकास को शिक्षा के केंद्र के रूप में भी करने की बात कही। आज काशी को मॉडल स्कूल, आईटीआई और ऐसे कई संस्थान भी मिले। सीआईपेट का सेंटर फॉर स्किलिंग एंड टेक्निकल सपोर्ट क्षेत्र के औद्योगिक विकास में मदद करेगा। श्री मोदी ने कहा कि उत्तर प्रदेश तेजी से देश के अग्रणी निवेश स्थान के रूप में उभर रहा है।

उन्होंने कहा कि कुछ वर्ष पहले तक जिस उत्तर प्रदेश में कारोबार करना मुश्किल माना जाता था, वह आज 'मेक इन इंडिया' के लिए पसंदीदा जगह बनता जा रहा है। श्री मोदी ने इसके लिए योगी सरकार को श्रेय दिया, क्योंकि हाल के दिनों में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए अथक रूप से ध्यान केंद्रित किया गया है। श्री मोदी ने डिफेंस कॉरिडोर, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे और गंगा एक्सप्रेसवे का हवाला देते हुए कहा कि हाल में इन्हें आगे बढ़ाया गया है।

कृषि बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण के लिए 1 लाख करोड़ रुपये

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि देश में कृषि बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण के लिए 1 लाख करोड़ रुपये का विशेष कोष बनाया गया है जिससे अब हमारी कृषि मंडियों को भी फायदा होगा। यह देश के कृषि बाजारों की व्यवस्था को आधुनिक और सुविधा संपन्न बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

उत्तर प्रदेश में नई विकास परियोजनाओं की लंबी सूची का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले भी राज्य के लिए योजनाएं और वित्त के लिए नियोजन किया जाता था, लेकिन फिर लखनऊ में वे अवरुद्ध हो जाते थे। उन्होंने विकास का परिणाम सभी तक पहुंचाने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की ऊर्जा और प्रयासों की प्रशंसा की।

श्री मोदी ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश में कानून का शासन है। माफिया राज और आतंकवाद, जो कभी नियंत्रण से बाहर हो रहे थे, अब कानून की गिरफ्त में हैं। जिस तरह से माता-पिता, बहनों और बेटियों की सुरक्षा को लेकर हमेशा डर और आशंका बनी रहती थी उस स्थिति में भी बदलाव आया है।

उन्होंने कहा कि आज उत्तर प्रदेश में सरकार भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद से नहीं, बल्कि विकास से चल रही है। उन्होंने कहा कि यही कारण है कि आज उत्तर प्रदेश में लोगों को सीधे योजनाओं का लाभ मिल रहा है। श्री मोदी ने कहा कि इसी कारण से नए उद्योग उत्तर प्रदेश में निवेश कर रहे हैं और रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं।

उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता की यह जिम्मेदारी है कि वह कोरोना को फिर ताकतवर न होने दे। उन्होंने आगाह किया कि महामारी की गति धीमी होने के बावजूद कोई भी लापरवाही बड़ी लहर को आमंत्रित कर सकती है। श्री मोदी ने सभी से प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करने और 'सभी के लिए टीका-सभी के लिए मुफ्त' अभियान के तहत टीका लगवाने का आह्वान किया। ■

जन-मिलन कार्यक्रम में लोगों से भेंट

भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने जनता से समन्वय और संवाद की कड़ी में 14 जुलाई को पार्टी कार्यालय के केन्द्रीय सभागार में आयोजित 'जन-मिलन कार्यक्रम' में लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं व मौके पर ही समाधान किया।

लद्दाख के लिए एक एकीकृत बहुउद्देश्यीय बुनियादी ढांचा विकास निगम की स्थापना को मिली मंजूरी

गत 22 जुलाई को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख के लिए एक एकीकृत बहुउद्देश्यीय बुनियादी ढांचा विकास निगम की स्थापना को मंजूरी दे दी। मंत्रिमंडल ने निगम के लिए 1,44,200 - 2,18,200 रुपये के वेतनमान के साथ प्रबंध निदेशक का एक पद सृजित करने को भी मंजूरी दी।

निगम का अधिकृत शेयर कैपिटल 25 करोड़ रुपये होगा और आवर्ती व्यय लगभग 2.42 करोड़ रुपये प्रति वर्ष होगा। यह एक नया प्रतिष्ठान है। वर्तमान में नवगठित केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख के भीतर ऐसा कोई संगठन नहीं है। इस स्वीकृति में रोजगार सृजन के लिए एक अंतर्निहित क्षमता है, क्योंकि निगम विभिन्न प्रकार की विकास संबंधी गतिविधियों को शुरू करेगा। निगम उद्योग, पर्यटन, परिवहन और स्थानीय तथा हस्तशिल्प के उत्पादों के विपणन के लिए काम करेगा। लद्दाख में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए निगम मुख्य निर्माण एजेंसी के रूप में भी काम करेगा।

निगम की स्थापना से केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख का समावेशी और एकीकृत विकास होगा। साथ ही, यह पूरे क्षेत्र और केंद्रशासित प्रदेश की आबादी के सामाजिक-आर्थिक विकास को सुनिश्चित करेगा। विकास का प्रभाव बहुआयामी होगा। यह भविष्य में मानव संसाधनों के विकास और उसके बेहतर उपयोग में मदद करेगा। यह वस्तुओं और सेवाओं के घरेलू उत्पादन को बढ़ाएगा और उनकी सुचारू आपूर्ति को सुगम बनाएगा। इस प्रकार, यह स्वीकृति 'आत्मनिर्भर भारत' के लक्ष्य को साकार करने में मदद करेगी।

पृष्ठभूमि

i. जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के अनुसार तत्कालीन जम्मू-कश्मीर राज्य के पुनर्गठन के परिणामस्वरूप केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख (विधानमंडल के बिना) 31 अक्टूबर, 2019 को अस्तित्व में आया।

ii. जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा 85 के तहत एक सलाहकार समिति का गठन किया गया था, जो तत्कालीन जम्मू-कश्मीर राज्य की संपत्ति और देनदारियों के केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख के बीच विभाजन के संबंध में सिफारिशें करने के लिए थी। उक्त समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एकीकृत विकास निगम लिमिटेड (एएनआईआईडीसीओ) की तर्ज पर लद्दाख एकीकृत बुनियादी ढांचा विकास निगम लिमिटेड की स्थापना के लिए सिफारिश की है, जिसमें लद्दाख की खास जरूरतों के अनुसार विभिन्न विकासात्मक गतिविधियों को संचालित करने के लिए एक उपयुक्त जनादेश दिया गया हो।

iii. तदनुसार, केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख ने इस मंत्रालय को केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख में निगम की स्थापना के लिए एक प्रस्ताव भेजा, जिसकी सिफारिश अप्रैल, 2021 में वित्त मंत्रालय की स्थापित किए जाने संबंधी समिति (सीईई) द्वारा की गई थी। ■

न्यायपालिका के लिए बुनियादी ढांचे से जुड़ी सुविधाओं के विकास के लिए केन्द्र प्रायोजित योजना को मिली मंजूरी

गत 14 जुलाई को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने न्यायपालिका के लिए बुनियादी ढांचे से जुड़ी सुविधाओं के विकास के लिए केन्द्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) को 01 अप्रैल, 2021 से लेकर 31 मार्च, 2026 तक और पांच वर्षों के लिए जारी रखने की मंजूरी दी। इस पर आने वाली कुल 9,000 करोड़ रुपये की लागत में केन्द्र सरकार की हिस्सेदारी 5,357 करोड़ रुपये की होगी, जिसमें ग्राम न्यायालय योजना और न्याय दिलाने एवं कानूनी सुधार से जुड़े एक राष्ट्रीय मिशन के जरिए मिशन मोड में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 50 करोड़ रुपये की लागत भी शामिल है।

इस प्रस्ताव से जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायिक अधिकारियों के लिए 3800 कोर्ट हॉल और 4000 आवासीय इकाइयों (नई और वर्तमान में चल रही, दोनों किस्म की परियोजनाओं), वकीलों के लिए 1450 हॉल, 1450 शौचालय परिसरों और 3800 डिजिटल कंप्यूटर कक्षों के निर्माण में मदद मिलेगी। यह देश में न्यायपालिका के कामकाज एवं प्रदर्शन को बेहतर बनाने में मददगार साबित होगा और नए भारत के लिए बेहतर न्यायालयों के निर्माण की दिशा में एक नया कदम होगा।

केन्द्रीय मंत्रिमण्डल ने 50 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ 5 वर्षों की अवधि के लिए आवर्ती और अनावर्ती अनुदानों को प्रमाणित करके ग्राम न्यायालयों को समर्थन देने के निर्णय को भी मंजूरी दी।

हालांकि, अधिसूचित ग्राम न्यायालयों का संचालन शुरू होने और न्याय विभाग के ग्राम न्यायालय पोर्टल पर न्यायाधिकारियों की नियुक्ति किये जाने और इस बारे में रिपोर्ट दिए जाने के बाद ही राज्यों को धन जारी किया जाएगा। ■

रक्षा मंत्री ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित शिकायत प्रबंधन के एप्लिकेशन का शुभारंभ किया

रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 15 जुलाई, 2021 को नई दिल्ली में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई)-संचालित शिकायत प्रबंधन एप्लिकेशन का शुभारंभ किया जिसको रक्षा मंत्रालय ने आईआईटी-कानपुर की मदद से विकसित किया है।

यह शिकायत निवारण में सुधार के लिए विकसित की गई पहली कृत्रिम बुद्धिमता आधारित प्रणाली है। इस पहल के अंतर्गत विकसित एआई टूल में शिकायत में लिखी बातों के आधार पर शिकायत को समझने की क्षमता है। नतीजतन यह दोहराई जाने वाली शिकायतों या स्पैम की पहचान स्वचालित रूप से कर सकता है। शिकायत के अर्थ के आधार पर यह विभिन्न श्रेणियों की शिकायतों को वर्गीकृत कर सकता है, भले ही ऐसी खोज के लिए सामान्य रूप से उपयोग किए जाने वाले कीवर्ड शिकायत में मौजूद न हों।

यह एक श्रेणी में शिकायतों के भौगोलिक विश्लेषण की सुविधा प्रदान करता है जिसमें यह विश्लेषण भी शामिल है कि शिकायत का संबंधित कार्यालय द्वारा ठीक प्रकार से निपटारा किया गया या नहीं। आसान उपयोगकर्ता-अनुकूल सर्च करने की सुविधा उपयोग करने वाले को प्रबंधन आवश्यकताओं के आधार पर अपने प्रश्नों/श्रेणियों को तैयार करने और पूछे गए प्रश्न के आधार पर प्रदर्शन का परिणाम प्राप्त करने में सक्षम बनाती है।

यह देखते हुए कि प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) के सीपीजीआरएएमएस पोर्टल पर लाखों शिकायतें प्राप्त होती हैं, इस एप्लिकेशन का शिकायतों की प्रकृति को समझने में तथा जहां से वह शिकायतें आ रही हैं, उन स्थानों को समझने में बहुत उपयोग होगा तथा उन नीतिगत बदलावों को करने में मदद मिलेगी जो इन शिकायतों को दूर करने हेतु प्रणालीगत सुधार करने के लिए लाए जा सकते हैं। इस अवसर पर बोलते हुए रक्षा मंत्री ने एप्लिकेशन को सुशासन का परिणाम बताया, जो सरकार और शिक्षाविदों के बीच बढ़ते तालमेल को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि यह पहल सरकार का एक और जन-केंद्रित सुधार है जिसका उद्देश्य बड़े पैमाने पर लोगों को सशक्त बनाना है।

श्री राजनाथ सिंह ने लोक शिकायत निवारण प्रणाली के सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) की सराहना करते हुए कहा कि लोगों की शिकायतों का समाधान करना अपने आप में एक महान सेवा है। उन्होंने कहा कि आईआईटी कानपुर जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों की सक्रिय भागीदारी इस प्रणाली को और मजबूत करेगी। ■

राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को टीके की 45.73 करोड़ से अधिक खुराक प्रदान की गईं

केंद्र सरकार पूरे देश में कोविड-19 टीकाकरण की रफ्तार तेज करने और दायरा बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। कोविड-19 टीके की व्यापक उपलब्धता से जुड़ा नया चरण 21 जून, 2021 से शुरू हुआ है। टीकाकरण अभियान के जरिये ज्यादा टीकों की उपलब्धता के साथ राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों को टीकाकरण उपलब्धता की अग्रिम जानकारी देकर तेज किया गया है ताकि टीकों को लेकर राज्य और केंद्रशासित प्रदेश बेहतर योजना बना सकें और टीकों की आपूर्ति शृंखला सुव्यवस्थित की जा सके।

राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत भारत सरकार राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को निःशुल्क कोविड टीके उपलब्ध कराकर उनकी मदद कर रही है। सबको टीका उपलब्ध कराने से जुड़े कोविड-19 टीकाकरण अभियान के नए चरण के तहत केंद्र सरकार देश में टीका विनिर्माताओं द्वारा उत्पादित 75 प्रतिशत टीके खरीदेगी और उनकी राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों को (निःशुल्क) आपूर्ति करेगी।

भारत सरकार ने अब तक राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को कोविड टीके की 45.73 करोड़ से अधिक खुराक (45,73,30,110) सभी स्रोतों के माध्यम से प्रदान की है। इसके अलावा टीके की 24,11,000 खुराक प्रक्रियारत हैं। 27 जुलाई की सुबह आठ बजे उपलब्ध आंकड़े के अनुसार इनमें अपव्यय सहित कुल 43,80,46,844 खुराक की खपत हुई है।

राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों और निजी अस्पतालों के पास अब भी टीके की 2.28 करोड़ से अधिक (2,28,27,959) खुराक उपलब्ध हैं जो बची हुई हैं, जिनका अभी इस्तेमाल किया जाना है। ■

प्रधानमंत्री ने वाराणसी में इंटरनेशनल को-ऑपरेशन एंड कन्वेंशन सेंटर 'रुद्राक्ष' का किया उद्घाटन

गत 15 जुलाई को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने वाराणसी में इंटरनेशनल को-ऑपरेशन एंड कन्वेंशन सेंटर 'रुद्राक्ष' का उद्घाटन किया, जिसका जापान की सहायता से निर्माण किया गया है। उसके बाद उन्होंने बीएचयू की मातृ और शिशु स्वास्थ्य इकाई का निरीक्षण किया।

इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि कोविड के बावजूद काशी में विकास की गति बरकरार रही। उन्होंने कहा कि 'इंटरनेशनल को-ऑपरेशन एंड कन्वेंशन सेंटर-रुद्राक्ष' इस रचनात्मकता और गतिशीलता का परिणाम है। उन्होंने कहा कि इस केंद्र से भारत और जापान के बीच मजबूत जुड़ाव का पता चलता है। उन्होंने इस कन्वेंशन सेंटर के निर्माण में मदद करने के लिए जापान के प्रयासों की सराहना की।

श्री मोदी ने याद किया कि जापान के प्रधानमंत्री श्री शुगा योशीहिदे मुख्य कैबिनेट सचिव थे। तब से लेकर जापान के प्रधानमंत्री बनने तक वह व्यक्तिगत रूप से इस परियोजना से जुड़े रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि भारत के प्रति उनके अपनेपन के लिए हर भारतीय उनका आभारी है।

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने याद दिलाया कि जापान के पूर्व प्रधानमंत्री श्री शिंजो आबे का भी आज के कार्यक्रम से नजदीकी जुड़ाव है। उन्होंने उस क्षण को याद किया, जब उनकी जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री शिंजो आबे के साथ रुद्राक्ष की योजना पर चर्चा हुई थी, जब वह काशी आए थे।

श्री मोदी ने कहा कि इस इमारत में आधुनिकता की चमक और संस्कृति की आभा दोनों मौजूद हैं, इसमें भारत जापान संबंधों के संयोजन के साथ ही भविष्य में सहयोग की संभावनाएं भी छिपी हुई हैं। श्री मोदी ने कहा कि उनकी जापान यात्रा से इस प्रकार के जनता से जनता के बीच संबंधों की परिकल्पना होती है और रुद्राक्ष व अहमदाबाद में जेन गार्डन जैसी परियोजनाएं इसी संबंध की प्रतीक हैं।

प्रधानमंत्री ने आज सामारिक और आर्थिक दोनों क्षेत्रों में भारत के सबसे भरोसेमंद दोस्त होने के लिए जापान की सराहना की। उन्होंने कहा कि जापान के साथ भारत की दोस्ती को पूरे क्षेत्र में सबसे ज्यादा स्वाभाविक भागीदारियों में से एक के रूप में देखा जाता है। भारत और जापान का मानना है कि हमारा विकास हमारे उल्लास से संबंद्ध होना चाहिए। यह विकास चहुंमुखी होना चाहिए, सभी के लिए होना चाहिए और सर्वव्यापी होना चाहिए।

कोविड के बावजूद काशी में विकास की गति बरकरार रही। 'इंटरनेशनल को-ऑपरेशन एंड कन्वेंशन सेंटर- रुद्राक्ष' इस रचनात्मकता और गतिशीलता का परिणाम है। इस केंद्र से भारत और जापान के बीच मजबूत जुड़ाव का पता चलता है

संगीत और कला बनारस के रोम-रोम में मौजूद

श्री मोदी ने कहा कि गाने, संगीत और कला बनारस के रोम-रोम में मौजूद है। यहां गंगा के घाटों पर कई कलाओं का विकास हुआ है, ज्ञान शिखर पर पहुंच गया है और मानवता से संबंधित कई गंभीर विचार सामने आए हैं। यही वजह है कि बनारस संगीत, धर्म, ज्ञान एवं विज्ञान की भावना का बड़ा वैश्विक केंद्र बन सकता है। उन्होंने कहा कि यह केंद्र एक बड़ा सांस्कृतिक केंद्र और विभिन्न लोगों को एकजुट करने का माध्यम बन जाएगा।

श्री मोदी ने कहा कि पिछले 7 साल में काशी को कई विकास परियोजनाओं से सुशोभित किया गया है, तो यह श्रृंगार बिना रुद्राक्ष के कैसे पूरा हो सकता था? अब काशी जो वास्तविक शिव है, ने इस रुद्राक्ष को धारण कर लिया है तो काशी का विकास और भी ज्यादा चमकेगा और काशी की सुंदरता और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। ■

संसद के मानसून सत्र के दौरान पूरे किए जाएंगे 31 सरकारी कार्य

छह विधेयक अध्यादेशों की जगह लेंगे

संसद का मानसून सत्र 19 जुलाई से प्रारंभ हुआ और 13 अगस्त तक जारी रहेगा। सत्र की 19 बैठकों के दौरान 31 सरकारी विषय (29 विधेयक और 2 वित्तीय विषयों सहित) रखे जाएंगे। छह विधेयक अध्यादेशों की जगह लेंगे। मानसून सत्र, 2021 के दौरान पेश किए जाने वाले विधेयकों की सूची निम्न है:

I– विधायी कार्य

- अधिकरण सुधार (सेवा का युक्तिकरण और शर्तें) विधेयक, 2021- अध्यादेश की जगह लेने के लिए
- दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) विधेयक, 2021- अध्यादेश की जगह लेने के लिए
- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए आयोग विधेयक, 2021- अध्यादेश की जगह लेने के लिए
- आवश्यक रक्षा सेवा विधेयक, 2021- अध्यादेश की जगह लेने के लिए
- भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद (संशोधन) विधेयक, 2021- अध्यादेश की जगह लेने के लिए
- होम्योपैथी केंद्रीय परिषद (संशोधन) विधेयक, 2021- अध्यादेश की जगह लेने के लिए
- डीएनए प्रौद्योगिकी (उपयोग और अनुप्रयोग) विनियमन विधेयक, 2019
- फैक्टरिंग विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2020
- सहायक प्रजनन तकनीक (विनियमन) विधेयक, 2020
- अभिभावक और वरिष्ठ नागरिक देखरेख एवं कल्याण (संशोधन) विधेयक, 2019
- राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान विधेयक, 2019, जैसाकि राज्य सभा द्वारा पारित किया गया
- नौवहन के लिए समुद्री सहायता विधेयक, 2021, जैसाकि लोकसभा द्वारा पारित किया गया
- किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2021, जैसाकि लोकसभा द्वारा पारित किया गया
- सरोगेसी (विनियमन) विधेयक, 2019
- कोयला क्षेत्र (अधिग्रहण एवं विकास) संशोधन विधेयक, 2021
- चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कॉस्ट और वर्क्स अकाउंटेंट्स तथा कंपनी सेक्रेटरीज (संशोधन) विधेयक, 2021
- सीमित दायित्व भागीदारी (संशोधन) विधेयक, 2021
- कैंटोनमेंट विधेयक, 2021
- भारतीय अंटार्कटिका विधेयक, 2021

- केंद्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021
- भारतीय वन प्रबंधन संस्थान विधेयक, 2021
- पेंशन कोष विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2021
- जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) विधेयक, 2021
- भारतीय समुद्री मात्स्यिकी विधेयक, 2021
- पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (संशोधन) विधेयक, 2021
- अंतर्देशीय पोत विधेयक, 2021
- विद्युत (संशोधन) विधेयक, 2021
- मानव तस्करी (रोकथाम, संरक्षण और पुनर्वास) विधेयक, 2021
- नारियल विकास बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2021

II– वित्तीय कार्य

- 2020-21 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों पर प्रस्तुतिकरण, चर्चा और मतदान तथा संबंधित विनियोग विधेयक को पेश करना, विचार करना और पारित करना।
- 2017-18 के लिए अनुदानों की अतिरिक्त मांगों पर प्रस्तुतिकरण, चर्चा और मतदान व संबंधित विनियोग विधेयक को पेश करना, विचार करना और पारित करना। ■

साल 2021 में जम्मू-कश्मीर में आतंकी घटनाओं में बड़ी गिरावट

जम्मू-कश्मीर में इस साल आतंकवाद से जुड़ी घटनाओं में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई, जो पिछले साल 30 जून के 105 मामलों के मुकाबले इस साल 16 जुलाई, 2021 तक गिरकर 67 रह गई। इस दौरान स्थानीय आतंकियों की भर्ती में भी कमी देखी गई, 16 जुलाई तक आतंकी भर्ती के 57 मामलों सामने आये, जबकि 2020 की पहली छमाही में यह आंकड़ा 73 था।

केंद्रीय सुरक्षा प्रतिष्ठान के सूत्रों के मुताबिक इन सकारात्मक बदलावों के लिए केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन द्वारा जम्मू-कश्मीर के युवाओं के लिए उद्यमशीलता की पहल और खेल जैसी मनोरंजक गतिविधियों में शामिल करने के लिए ठोस प्रयासों को प्रमुख वजह माना जा रहा है इस साल 16 जुलाई तक आतंकवादी संगठनों में शामिल होने वाले 57 स्थानीय आतंकवादियों में से 34 को मार गिराया गया और 11 ने आत्मसमर्पण कर दिया। अब केवल 12 नये आतंकवादी इस क्षेत्र में सक्रिय हैं।

इस साल 16 जुलाई तक लगभग आधा दर्जन सुरक्षा बलों के जवान शहीद हुए है, जबकि 2020 में 62 सुरक्षाकर्मी शहीद हुए थे। साथ ही, इस साल (16 जुलाई तक) आतंकवादियों ने 14 नागरिक

को मौत के घाट उतारा, जबकि पिछले साल 37 नागरिक मारे गए थे। आतंकवादी संगठनों में शामिल होने वाले स्थानीय युवाओं की संख्या में गिरावट के बारे में बताते हुए एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बताया कि युवाओं को स्वरोजगार के लिए वाणिज्यिक वाहनों की पेशकश, कौशल विकास पहल और खेल और अन्य मनोरंजक गतिविधियों के माध्यम से रचनात्मक जुड़ाव जैसे उपायों के कारण यह परिणाम देखने को मिल रहे हैं। ■

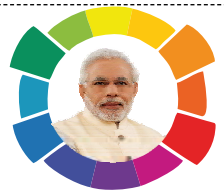

BECOME PART OF A VIBRANT IDEOLOGICAL MOVEMENT
BECOME PROUD MEMBER OF 'KAMAL SANDESH'

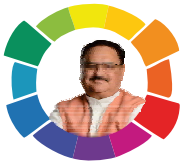

SUBSCRIPTION DETAILS

Name : .....

Address : .....

..... Pin : .....

Phone : ..... Mobile : (1)..... (2).....

E-mail : .....

SUBSCRIPTION TYPE	One Year	₹350/-	☐	Life Time (English or Hindi)	₹3000/-	☐
	Three Years	₹1000/-	☐	Life Time (English+Hindi)	₹5000/-	☐

(DETAIL OF THE PAYMENT)

Cheque/Draft No. :..... Date :..... Bank : .....

Note : * DD/Cheque will be made in favour of "**Kamal Sandesh**"
* Money order and Cash accepted with details

(Subscriber's Signature)

KAMAL SANDESH

SEND YOUR DD/CHEQUE ON THIS ADDRESS
Dr. Mookerji Smruti Nyas, PP-66, Subramania Bharati Marg, New Delhi-110003
Ph.: 011-23381428 **Fax:** 011-23387887 **E-mail:** kamalsandesh@yahoo.co.in

KAMAL SANDESH - DEDICATED TO NATIONAL CAUSE

नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोविड–19 की स्थिति पर उत्तर–पूर्वी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत करते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्रिमंडल की एक बैठक की अध्यक्षता करते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से टोक्यो ओलंपिक जाने वाले भारतीय एथलीटों के दल के साथ बातचीत करते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

वाराणसी (उत्तर प्रदेश) में इंटरनेशनल को–ऑपरेशन एंड कन्वेंशन सेंटर–रुद्राक्ष के उद्घाटन अवसर पर संबोधित करते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

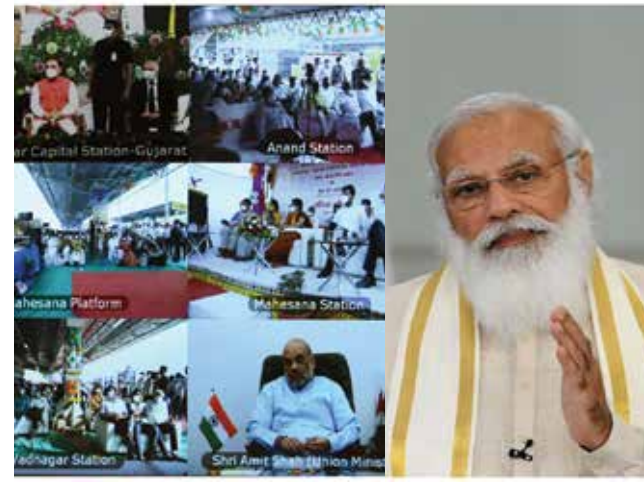

नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुजरात में कई विकास परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करने के बाद संबोधित करते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

कमल संदेश

अब इंटरनेट पर भी उपलब्ध

लॉग इन करें:

www.kamalsandesh.org

राष्ट्रीय विचार की प्रतिनिधि पाक्षिक पत्रिका

@Kamal.Sandesh @KamalSandesh

kamal.sandesh KamalSandeshLive

प्रेषण तिथि: (i) 1-2 चालू माह (ii) 16-17 चालू माह
डाकघर: लोदी रोड एचओ., नई दिल्ली **"रजिस्टर्ड"**
36 पृष्ठ कवर सहित
आर.एन.आई. DELHIN/2006/16953
डी.एल. (एस)-17/3264/2021-23
Licence to Post without Prepayment
Licence No. U(S)-41/2021-23

छायाकार: अजय कुमार सिंह